सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 65, नई दिल्ली । शुक्रवार, 17 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यदि आप बहाने बनाते हैं मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते।

03 मालीवाल के केस में दिल्ली पुलिस आई एक्शन में

06 मोदी की मुसलमानों से आत्ममंथन करने की अपील

08 ज़िला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में सुनी जन समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश

सड़क पर गाड़ी दौड़ाना सांप और सीढ़ी का खेल के समान

सड़कों पर चलना अक्सर सांप और सीढ़ी का खेल खेलने जैसा महसूस हो सकता है। प्रत्येक यात्रा आपके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने का वादा करती है, लेकिन केवल तभी जब आप रास्ते में खतरनाक ₹सांपों₹ से बचें। क्लासिक बोर्ड गेम की तरह, जहां पासे का प्रत्येक रोल आपको जीत के करीब ला सकता है या आपको फिर से शुरू करने के लिए सांप को नीचे गिरा सकता है, सुरक्षित आगमन सुनिश्चित करने के लिए ड्राइविंग में सावधानी और रणनीति दोनों की आवश्यकता होती है।

स्नेक एंड लैडर्स में, खिलाड़ी सीढ़ी पर चढ़ने और सांपों से बचने के लिए भाग्य और सावधानीपूर्वक गतिविधियों पर भरोसा करते हैं। इसी तरह, सड़क सुरक्षा कई कारकों पर निर्भर करती है: यातायात नियमों का पालन, सतर्कता और कभी-कभी, थोड़ा भाग्य। आइए सुरक्षित ड्राइविंग के प्रमुख पहलुओं को समझने के लिए इस सादृश्य को और देखें।

सीढ़ियाँ: सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सकारात्मक कार्य

यातायात नियमों का पालन करना: जिस प्रकार सीढ़ियाँ खिलाड़ियों को जल्दी से बोर्ड पर चढ़ने में मदद करती हैं, उसी प्रकार यातायात नियमों का पालन करने से आपकी यात्रा सुव्यवस्थित हो सकती है। गति सीमा, रुकने के संकेत और ट्रैफ़िक सिग्नल ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन कानूनों का पालन सुचारू और पूर्वानुमानित यातायात प्रवाह सुनिश्चित करता है।

रक्षात्मक ड्राइविंग: अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के कार्यों का पूर्वानुमान लगाना और प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहना आपको दुर्घटनाओं से बचने में मदद कर सकता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण एक ऐसी सीढ़ी खोजने के समान है जो आपको संभावित खतरों से दूर, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

नियमित वाहन रखरखाव: अपने वाहन को अच्छी स्थिति में रखने से खराबी और दुर्घटनाओं का खतरा कम हो जाता है। ब्रेक, टायर और लाइट की नियमित जांच को सुरक्षित यात्रा की ओर सीढ़ी चढ़ने के रूप में देखा जा सकता है।

सीट बेल्ट पहनना: सीट बेल्ट एक सरल लेकिन प्रभावी सुरक्षा उपाय है। झुकना एक सीढ़ी को पकड़ने जैसा है जो टकराव की स्थिति में गंभीर चोट को रोक सकता है।

ध्यान भटकाने से बचना: सड़क पर ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है। वाहन चलाते समय संदेश भेजने या खाने जैसी विकर्षणों के कारण त्रुटियाँ हो सकती हैं। एकाग्रता आपको अपने लक्ष्य पर बने रहने में मदद करती है, ठीक उसी तरह जैसे अनावश्यक पासा पलटने से बचना जो आपको साँप के पास ले जा सकता है।

साँप: सड़क पर खतरे और गलत कदम

तेज़ गति: सीमा से अधिक गति चलाना सबसे खतरनाक ड्राइविंग व्यवहारों में से एक है।

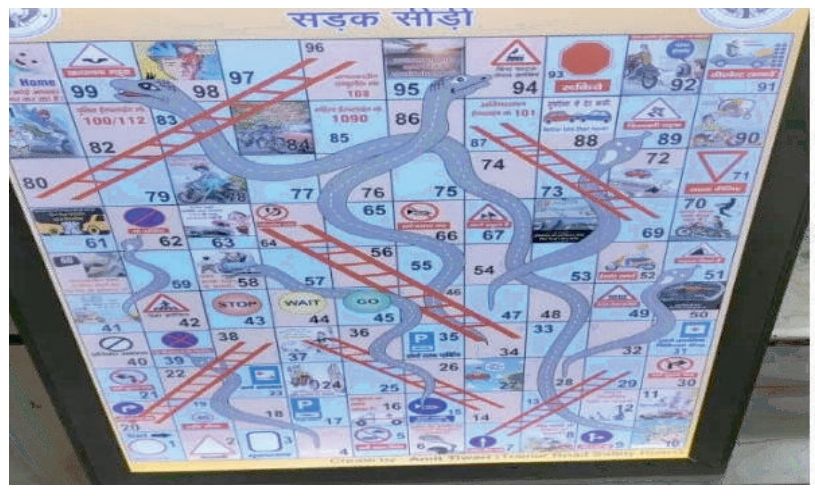

तेज़ गति से गाड़ी चलाना एक साँप का सामना करने जैसा है जो आपको वापस भेज देता है; इससे नियंत्रण खोने और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है।

प्रभाव में गाड़ी चलाना: शराब और नशीली दवाएं निर्णय और प्रतिक्रिया समय को ख़राब करती हैं। नशे में गाड़ी चलाना एक गंभीर समस्या है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर कानूनी परिणाम और दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

मौसम की स्थिति को नज़रअंदाज़ करना: बारिश, बर्फ़ या कोहरे जैसे प्रतिकूल मौसम में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। इन स्थितियों को नजरअंदाज करना सांप पर पैर रखने के समान है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

थकान: थके हुए होकर गाड़ी चलाने से आपकी तुरंत प्रतिक्रिया करने और सही निर्णय लेने की क्षमता ख़राब हो जाती है। थकान आसानी से गलतियों का कारण बन सकती है, जैसे बिना ध्यान दिए पासा पलटने से आप साँप के पास पहुँच सकते हैं।

आक्रामक ड्राइविंग: रोड रेज और आक्रामक व्यवहार, जैसे कि पीछे से गाड़ी चलाना या ट्रैफ़िक के बीच से गुजरना, दुर्घटनाओं के जोखिम को काफी बढ़ा देता है। ये क्रियाएं लापरवाह खेल के कारण बार-बार सांपों पर उतरने के बराबर हैं।

सुरक्षित ड्राइविंग, स्नेक एंड लैडर्स में जीत की तरह, जोखिमों को कम करने और स्मार्ट विकल्प चुनने के बारे में है। हालाँकि भाग्य एक छोटी भूमिका निभाता है, अधिकांश सफलता आपके कार्यों और निर्णयों पर निर्भर करती है। जोखिमों (सांपों) को समझने और कम करने और सुरक्षित प्रथाओं (सीढ़ियों) को अपनाने से, आप सड़कों पर अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वास से चल सकते हैं।

याद रखें, आपकी प्रत्येक यात्रा पासे का एक नया रोल है। सुनिश्चित करें कि आपका प्रत्येक कदम आपको अनावश्यक असफलताओं का सामना किए बिना अपने गंतव्य के करीब ले जाए। सुरक्षित ड्राइविंग का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है; यह यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि सड़क पर बाकी सभी लोग भी अपनी पहुंच तक पहुंचें। साँप और सीढ़ी की तरह, कुंजी चतुराई से खेलना और सतर्क रहना है।

डॉ अंकुर शरण,
roadsafetysquad@gmail.com

इस साल 41 करोड़ से ज्यादा हो सकती है देश में हवाई यात्रियों की संख्या

परिवहन विशेष न्यूज

इक्रा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के साथ-साथ दिल्ली हैदराबाद और कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के परिचालकों के बीच किए सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। इक्रा में कॉरपोरेट रेटिंग के उपाध्यक्ष एवं क्षेत्र प्रमुख विनय कुमार जी. का कहना है भारतीय हवाई अड्डा यात्रियों की संख्या में सुधार अन्य प्रमुख वैश्विक समकक्षों की तुलना में सबसे अधिक में से एक है।

नई दिल्ली। देश में जैसे जैसे विकास को गति मिल रही है और नए-नए एयरपोर्ट सर्विस में आ रहे हैं, हवाई यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष यानी वर्ष 2024-25 में देश में हवाई यात्रियों की संख्या 40.7 से 41.8 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। पिछले वित्त 2023-24 में यह आंकड़ा 37.64 करोड़ था। यह कोविड-19 वैश्विक महामारी से पहले की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

इक्रा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में हवाई यातायात में सालाना आधार पर करीब आठ से 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यात्रियों की संख्या 40.7 से 41.8 करोड़ तक पहुंच सकती है। छुट्टियों के सीजन और व्यावसायिक यात्रा दोनों में मजबूत वृद्धि के साथ घरेलू क्षेत्र में नई जगहों तक पहुंच में सुधार और अंतरराष्ट्रीय यात्रा में निरंतर वृद्धि इसकी मुख्य वजह रहेगी।

रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में चुनिंदा हवाई अड्डा परिचालकों का सालाना आधार पर राजस्व कुल 15-17 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

इक्रा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के साथ-साथ दिल्ली, हैदराबाद और कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के परिचालकों के बीच किए सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है।

इक्रा में कॉरपोरेट रेटिंग के उपाध्यक्ष एवं क्षेत्र प्रमुख विनय कुमार जी. का कहना है, "भारतीय हवाई अड्डा यात्रियों की संख्या में सुधार अन्य प्रमुख वैश्विक समकक्षों की तुलना में सबसे अधिक में से एक है। कैलेंडर वर्ष 2023 में वैश्विक यात्री यातायात में भारत की हिस्सेदारी 4.2 प्रतिशत, जबकि 2019 में 3.8 प्रतिशत थी।"

उन्होंने कहा, "मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ नए मार्गों के जुड़ने से भारतीय यात्री यातायात कोविड-पूर्व के मुकाबले 106 प्रतिशत तक पहुंच गया। भारतीय हवाई यात्री यातायात के वैश्विक रुझान से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है।"

पच्छिम बंगाल परिवहन अधिकारी को बस जांच करना महँगा हुआ

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर: सही कागजात के साथ बस जाँच के मामले में पश्चिम बंगाल परिवहन अधिकारी का परीशानी बढ़ गया है। मालिक द्वारा ट्वीट कर पश्चिम बंगाल सरकार को जानकारी देने के बाद परिवहन अधिकारी सतर्क हो गये। पकड़े जाने के बाद संबंधित अधिकारी विमान से भुवनेश्वर आये, मालिक के घर की तलाशी ली, माफी मांगी और जुर्माना वापस कर दिया। इतना ही नहीं; शिष्टाचार के तौर पर, बस मालिक अधिकारी को मनोरंजन के लिए एक सितारा होटल में घर ले गया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की जिद से भयभीत अधिकारी केवल दाल, चावल और आलू लेकर खाना खाया। कल घटी ऐसी ही एक दिलचस्प घटना आज बरमूडा बस टर्मिनल इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल से कुछ पर्यटक एक साथ जगन्नाथ दर्शन के लिए ट्रेन से ओडिशा आए थे। जगन्नाथ ने मंदिर का दौरा किया और भुवनेश्वर के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा किया। फिर उन्होंने ट्रेन से लौटने के बजाय बस बुक की और पश्चिम बंगाल लौट आए। यात्री बस के वहां पहुंचने के बाद पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग के एक युवा परिवहन अधिकारी और एमवीआई ने कोलकाता के एक व्यस्त बाजार में बस की फिटनेस, प्रदूषण, परिधि, बीमा आदि की जांच की। अधिकारी के मांगने पर चालक ने लेन के सभी कागजात दिखाये। सारे कागजात जांचने के बाद भी परिवहन अधिकारी ने 1 लाख 80 हजार रुपये काट लिये.

जब बस चालक ने पूछा कि किस गलती का किराया देना होगा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टे खुलेआम धमकी दी कि पैसे दो नहीं तो गाड़ी जब्त कर ली जायेगी। गाड़ी के मालिक ने अधिकारी से फोन पर बात की लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि मालिक कार से पश्चिम बंगाल पहुंचा और परिवहन अधिकारियों से मिला। फिर भी वे कोई अच्छा कारण नहीं दिखा सके; लेकिन वह जुर्माना भरने का इंतजार कर रहा था। काफी समझाने के बाद भी बस मालिक ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बजाय, उन्होंने ट्रैफिक का पैसा नहीं देने पर वाहन जब्त करने की धमकी दी। परिणामस्वरूप, बस मालिक ने अपने दावे के अनुसार 1 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया। पैसे चुकाने के बाद बस का मालिक भुवनेश्वर लौट आया। बस मालिक ने बिना वजह इतने पैसे चुकाने पर अफसोस जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को ट्वीट के जरिए घटना की जानकारी दी। मामला परिवहन आयुक्त के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नतीजे से डरकर अधिकारी ने लेन नंबर से बस मालिक के घर का पता निकाला और 40 हजार रुपये हवाई खर्च कर कोलकाता से भुवनेश्वर आ गया। उसने बस मालिक से ऐसी गलती करने के लिए माफी मांगी और पैसे लौटा दिए।

पर्यावरण पाठशाला : गिव मी ट्रीज़ ट्रस्ट की प्रकृति शिक्षा पहल - अंकुर

वृक्षारोपण और प्रकृति शिक्षा के लिए समर्पित एक प्रतिष्ठित संगठन, गिव मी ट्रीज़ ट्रस्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रकृति शिक्षा के प्रमुख श्री विनीत वोहरा के नेतृत्व में, ट्रस्ट हजारों स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों तक पहुंच गया है, जिससे युवा मन में पर्यावरण के प्रति गहरी सराहना पैदा हुई है।

प्रकृति शिक्षा पहल:

हरियाली और हरित गतिविधियों को बढ़ावा देने में श्री विनीत वोहरा के अथक प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं। उनकी यात्राओं में अंतरराष्ट्रीय स्कूलों, पब्लिक स्कूलों, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों सहित कई शैक्षणिक संस्थानों का दौरा शामिल है। ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रकृति शिक्षा कार्यक्रमों में छात्रों के बीच प्रकृति के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई विभिन्न प्रकार की इंटरैक्टिव और शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं:

पर्यावरण सत्र:

पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं के महत्व पर आकर्षक चर्चाएँ और प्रस्तुतियाँ।

हर्बल बागवानी:

हर्बल पौधों को उगाने और उनके रखरखाव पर व्यावहारिक सत्र, छात्रों को विभिन्न जड़ी-बूटियों के लाभ और उपयोग सिखाना।

तितली बागवानी:

जैव विविधता को बढ़ावा देने और पारिस्थितिक तंत्र में तितलियों के जीवन चक्र और भूमिकाओं पर छात्रों को शिक्षित करने के लिए तितली-अनुकूल उद्यान बनाना।

इको ऑडिट:

छात्रों को अपने स्कूलों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने और हरित प्रथाओं को लागू करने में शामिल करना।

जैव एंजाइम बनाना:

जैविक कचरे से पर्यावरण-अनुकूल सफाई एजेंट बनाने पर कार्यशालाएँ।

जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक बनाना:

प्राकृतिक उर्वरक और कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया सिखाना, जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना।

माइक्रोग्रीन्स की खेती:

शहरी खेती के लाभों पर प्रकाश डालते हुए, पोषक तत्वों से भरपूर माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए व्यावहारिक गतिविधियाँ।

प्रकृति की सैर:

स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को देखने और उनकी सराहना करने के लिए निर्देशित पर्यटन।

बटरफ्लाई और ट्री वॉक:

तितली आवासों और विभिन्न वृक्ष प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली विशेष वॉक, जैव विविधता के बारे में छात्रों की समझ को बढ़ाती है।

हर्बल सत्र: विभिन्न जड़ी-बूटियों के औषधीय गुणों और पारंपरिक उपयोग पर गहन चर्चा।

भाग लेने वाले स्कूल:

भाग लेने वाले स्कूलों की व्यापक सूची ट्रस्ट की पहल के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है। उल्लेखनीय संस्थानों में शामिल हैं:

पाथवेज स्कूल
प्रोमेथियस स्कूल
दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस)
रयान इंटरनेशनल स्कूल
सर्वोदय विद्यालय
जे.पी. स्कूल
मॉडर्न स्कूल
जेनेसिस ग्लोबल स्कूल
केन्द्रीय विद्यालय
प्रज्ञान स्कूल
दिल्ली वर्ल्ड स्कूल
डीएवी स्कूल
जी.डी. गोयनका स्कूल
जीटीबी स्कूल
यूरो स्कूल
कल्याणवास स्कूल
केआईआईटी वर्ल्ड स्कूल
सेंट जेवियर स्कूल
माउंट ओलिंप स्कूल
नूतन मराठी स्कूल
लोटस वैली स्कूल
नोएडा इंटरनेशनल स्कूल
प्रिंस पब्लिक स्कूल
ब्राइट स्कॉलर स्कूल
सिल्वर बेल्स स्कूल
स्वामी विवेकानन्द ग्लोबल स्कूल
लिटिल फ्लावर्स स्कूल
बिड़ला विद्या निकेतन स्कूल
रोज़वुड स्कूल
सरस्वती बाल मंदिर स्कूल
बाल भवन स्कूल
टैगोर इंटरनेशनल स्कूल
हेरिटेज स्कूल

छात्रों पर प्रभाव: छात्रों ने इन शैक्षिक यात्राओं के दौरान उल्लेखनीय उत्साह और जिज्ञासा दिखाई है। वे व्यवहारिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और पर्यावरण की गहरी समझ रखते हैं। ट्रस्ट के कार्यक्रमों के माध्यम से, बच्चे न केवल पेड़ों और हरियाली के महत्व के बारे में सीख रहे हैं बल्कि टिकाऊ जीवन और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक भी बन रहे हैं।

श्री विनीत वोहरा के नेतृत्व में प्रकृति शिक्षा के प्रति गिव मी ट्रीज़ ट्रस्ट की प्रतिबद्धता पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। कई स्कूलों का दौरा करके और छात्रों को सार्थक हरित गतिविधियों में शामिल करके, ट्रस्ट पर्यावरणीय प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। यह पहल न केवल छात्रों के शैक्षिक अनुभव को समृद्ध करती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। Email at indiangreenbuddy@gmail.com

संस्कारशाला : बच्चों के लिए पूजा और सांस्कृतिक शिक्षा का महत्व

हमने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे, युवा पूजा समारोह में कम रुचि दिखाते हैं या उन्हें लगता है कि यह उनका काम या जिम्मेदारी नहीं है। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बुनियादी बातें साझा कर रहे हैं। संस्कारशाला के माध्यम से हमने बहुत सारे कार्यक्रम, ऑनलाइन गतिविधियाँ और शारीरिक गतिविधियाँ जैसे कि बाल हनुमान चालीसा, गौशाला दर्शन, कहानी सुनाना और हमारे धर्म पर बुनियादी प्रश्न और उत्तर आयोजित किए हैं। इसलिए बेहतर संभावनाओं के लिए कुछ व्यावहारिक बिंदु साझा कर रहा हूँ।

निरंतर वैश्वीकरण की दुनिया में, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना तेजी से आवश्यक हो गया है। इस संबंध को बनाए रखने के सबसे गहन तरीकों में से एक है पूजा का अभ्यास, एक पारंपरिक हिंदू अनुष्ठान जिसमें प्रार्थना, प्रसाद और देवताओं के प्रति समर्पण शामिल है। बच्चों के लिए, पूजा की मूल बातें सीखना और उनकी सांस्कृतिक जड़ों को समझना आध्यात्मिक विकास से लेकर पहचान की मजबूत भावना तक कई लाभ प्रदान कर सकता है।

पूजा को समझना

पूजा हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रथा है, जिसे अक्सर घर पर और विशेष त्योहारों और अवसरों के दौरान दैनिक रूप से किया जाता है। इसमें देवताओं को फूल, भोजन और प्रार्थना अर्पित करना शामिल है, जो भक्ति, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। पूजा घर पर किए जाने वाले साधारण अनुष्ठानों से लेकर मंदिरों में किए जाने वाले विस्तृत समारोहों तक भिन्न हो सकती है।

पूजा का महत्व

आध्यात्मिक विकास: पूजा में शामिल होने से बच्चों में आध्यात्मिकता की भावना और परमात्मा के साथ संबंध विकसित करने में मदद मिलती है। यह आंतरिक शांति और नैतिक आधार की भावना को बढ़ावा देता है।

सांस्कृतिक निरंतरता: पूजा अनुष्ठान सीखना यह सुनिश्चित करता है कि सांस्कृतिक परंपराएँ पीढ़ियों तक चलती रहें। इससे बच्चों को अपनी विरासत को समझने और उसकी सराहना करने में मदद मिलती है।

पारिवारिक जुड़ाव: पूजा अक्सर एक पारिवारिक गतिविधि होती है, जो सदस्यों को एक साझा आध्यात्मिक अनुभव में एक साथ लाती है। इससे पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं और स्थायी यादें बनती हैं।

नैतिक और नैतिक मूल्य: पूजा से जुड़ी कहानियाँ और शिक्षाएँ अक्सर महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएँ देती हैं। ये शिक्षाएँ बच्चों को एक मजबूत नैतिक आधार विकसित करने में मदद करती हैं।

मानसिक कल्याण: पूजा की ध्यानपूर्ण और दोहराव वाली प्रकृति शांत प्रभाव डाल सकती है, तनाव को कम कर सकती है और मानसिक कल्याण को बढ़ावा दे सकती है।

सांस्कृतिक शिक्षा की भूमिका

पहचान निर्माण: सांस्कृतिक प्रथाओं को समझने से बच्चों में पहचान की मजबूत भावना विकसित करने में मदद मिलती है। इससे उन्हें अपनी विरासत के प्रति जुड़ाव और गर्व का एहसास होता है।

विविधता का सम्मान: अपनी संस्कृति के बारे में सीखना बच्चों को अन्य संस्कृतियों का सम्मान करना और उनकी सराहना करना भी सिखा सकता है। इससे आपसी सम्मान और समझ का माहौल विकसित होता है।

आलोचनात्मक सोच: सांस्कृतिक शिक्षा बच्चों को परंपराओं और प्रथाओं के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे उन्हें अनुष्ठानों के पीछे के कारणों और आधुनिक समय में उनकी प्रासंगिकता को समझने में मदद मिलती है।

बच्चों को पूजा और सांस्कृतिक शिक्षा का परिचय कैसे दें

जल्दी शुरुआत करें: छोटी उम्र में ही बच्चों को सरल अनुष्ठानों और कहानियों से परिचित कराएं। सीखने को मनोरंजक बनाने के लिए रंगीन चित्रों, आकर्षक कहानियों और इंटरैक्टिव गतिविधियों का उपयोग करें।

संसाधनों का उपयोग करें: बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई पुस्तकों, वीडियो और शैक्षिक कार्यक्रमों का उपयोग करें। कई संसाधन सांस्कृतिक प्रथाओं को आयु-उपयुक्त और आकर्षक तरीके से समझाते हैं।

उन्हें शामिल करें: बच्चों को पूजा में भाग लेने दें। उन्हें इसमें शामिल होने का एहसास कराने के लिए फूलों की व्यवस्था करना या दीपक जलाने जैसी छोटी-छोटी जिम्मेदारियाँ दें।

त्यौहार मनाएँ: त्यौहारों को बच्चों को उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करें। प्रत्येक त्यौहार का महत्व समझाएं और उन्हें तैयारियों में शामिल करें।

प्रश्नों को प्रोत्साहित करें: ऐसे माहौल को बढ़ावा दें जहाँ बच्चे प्रश्न पूछने में सहज महसूस करें। उन्हें अनुष्ठानों के पीछे के महत्व और अर्थ को समझने में मदद करने के लिए स्पष्ट और विचारशील उत्तर प्रदान करें।

पूजा और सांस्कृतिक शिक्षा युवा मन के आध्यात्मिक और नैतिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों को शुरुआत से ही इन प्रथाओं से परिचित कराकर, हम अपनी समृद्ध विरासत का संरक्षण और सराहना सुनिश्चित करते हैं। यह उन्हें एक ऐसे सर्वांगीण व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करता है जो अपनी पहचान पर कायम है, विविधता का सम्मान करता है और मजबूत नैतिक मूल्यों से सुसज्जित है। संस्कृति के संरक्षक के रूप में, यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाएँ, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का सार फलता-फूलता रहे।

संस्कारशाला के बारे में

"संस्कारशाला बच्चों में सांस्कृतिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हमारे कार्यक्रम विरासत के बारे में सीखने को आकर्षक और सार्थक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि युवा दिमाग आधुनिक दुनिया के लिए तैयार होने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से अच्छी तरह परिचित हों।"

-अंकुर शरण

जीवन में सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो याद रखें महात्मा गांधी की ये बात

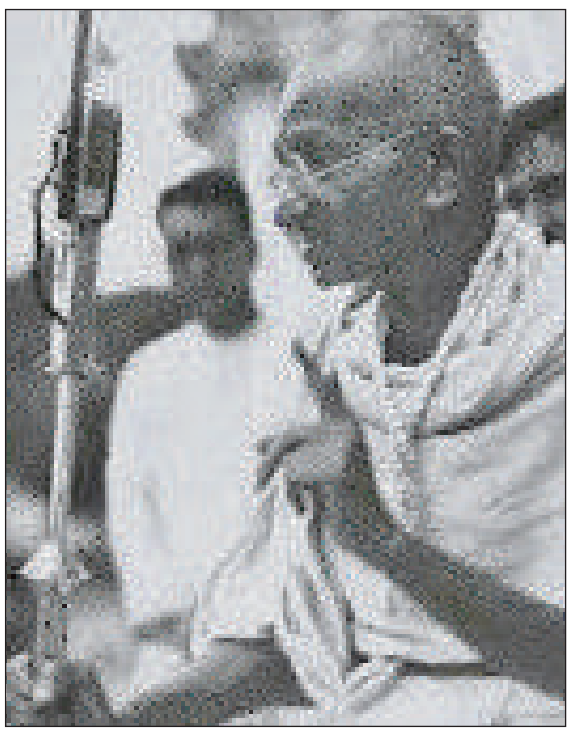

महात्मा गांधी नियम के बड़े पाबंद थे। कोई भी नियम काफी सोच-विचार के बाद ही बनाते थे। उनके साबरमती आश्रम में भोजन के समय उपस्थित होने के लिए दो

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Mahatma Gandhi Story: महात्मा गांधी नियम के बड़े पाबंद थे। कोई भी नियम काफी सोच-विचार के बाद ही बनाते थे। उनके साबरमती आश्रम में भोजन के समय उपस्थित होने के लिए दो बार घंटी बजती थी। नियमानुसार जो व्यक्ति दूसरी घंटी बजने तक भोजनशाला नहीं पहुंच पाता था, उसे दूसरी पंगत लगने तक बाहर बरामदे में ही खड़े रह कर इंतजार करना पड़ता था। बापू इसे लेट लतीफी की मीठी सजा कहते थे। दूसरी घंटी बजते ही रसोई घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे ताकि लेट आने वाले अंदर जा ही न सकें।

एक दिन ऐसा हुआ कि किसी जरूरी काम में फंसे होने की वजह से खुद बापू देरी से पहुंचे। दूसरी घंटी बजने के बाद रसोईघर का कार्यकर्ता दरवाजा बंद कर ही रहा था कि बापू आते दिखाई दिए। अब वह असमंजस में पड़ गया।

उसकी हिचक देख महादेव भई बोल पड़े, 'नियम तो नियम है। दरवाजा बंद कर लो।'

तब तक बापू दरवाजे के निकट आ गए थे, पर रसोई का दरवाजा बंद हो गया। बापू अनुशासित आश्रमवासी की तरह एक तरफ खड़े हो गए। तभी वहां हरिभाऊ उपाध्याय भी पहुंच गए।

उन्होंने वहां बापू को खड़े देखा तो बोले, ''आज तो आपने भी नियम तोड़ दिया। लेट हो गए आने में। अब मीठी सजा तो आपको भी भुगतनी ही पड़ेगी।'' बापू कोई प्रतिक्रिया देते, इससे पहले ही उन्होंने कहा, ''लेकिन आप खड़े क्यों हैं। रुकिए मैं आपके लिए कुर्सी लाता हूं।'' वह कुर्सी लेने जा ही रहे थे कि गांधी ने हाथ पकड़ कर उन्हें रोक लिया।

बापू बोले, ''क्या कर रहे हो ? देरी से आने वाले बैठते नहीं, यहां खड़े रह कर इंतजार करते हैं। मैं सजा भुगतने में कमजोर थोड़े ही हूं।''

फिर कुछ ठहर कर बोले, 'गलती हो जाए तो सजा पूरी भुगतनी चाहिए। जीवन में सच्चे आनंद को पाने के लिए यह जरूरी है।

मुक्ति का द्वार है चार धाम यात्रा

उत्तराखंड, जिसे देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, कई मंदिरों का घर है और पूरे वर्ष भक्तों का स्वागत करता है। उत्तराखंड में श्रद्धालु जिन अनगिनत धार्मिक स्थलों और मंदिरों का दौरा करते हैं, उनमें से सबसे प्रमुख चार धाम यात्रा है। हिंदू धर्म में चारधाम यात्रा का बहुत महत्त्व माना जाता है। इसी कारण हिंदू धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति कभी न कभी चार धाम की यात्रा पर जाना चाहता है। शास्त्रों के अनुसार चारधाम की यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हर साल की तरह इस साल भी 10 मई से उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया को उत्तराखंड चार धामों में से दो गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इनके बाद 10 मई को केदारनाथ और 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे।

ठंड और बर्फबारी की वजह से इन चार मंदिरों को शीतकाल के लिए बंद किया जाता है, गर्मी में जब मौसम ठीक हो जाता है, तब इन मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं। उत्तराखंड के चार धाम मंदिर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री और गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। ये दोनों धाम उत्तरकाशी जिले में हैं। शिव जी का 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। ये मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में है। भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम देश और उत्तराखंड के चार धामों में से एक है। ये मंदिर चामोली जिले में है।

यमुनोत्री धाम- यमुनोत्री धाम समुद्रतल से 3235 मी. की ऊंचाई पर है। यहां देवी यमुना का मंदिर है। यहीं यमुना नदी का उद्गम स्थल भी है। यमुनोत्री मंदिर टिहरी गढ़वाल के राजा प्रतापशाह ने बनवाया था। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार जयपुर की रानी गुलेरिया ने करवाया था।

गंगोत्री धाम- गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। यहां देवी गंगा का मंदिर है। समुद्रतल से ये मंदिर 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। ये स्थान जिला उत्तरकाशी से 100 किमी. की दूरी पर है। हर साल गंगोत्री मंदिर अप्रैल से अक्तूबर तक खोला जाता है। बाकी समय में यहां का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसीलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस क्षेत्र में राजा भागीरथ ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। शिवजी यहां प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उसका वेग शांत किया था। इसी क्षेत्र में गंगा की पहली धारा भी गिरी थी।

केदारनाथ धाम- केदारनाथ उत्तराखंड के चार धामों में तीसरे नंबर पर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां है और सबसे ऊंची जगह पर है। महाभारत काल में यहां शिवजी ने पांडवों को बेल के रूप में दर्शन दिए थे। ये मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर करीब 3,581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गौरीकुंड से करीब 16 किमी. की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं और 9वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने मौजूदा मंदिर बनवाया था।

बद्रीनाथ धाम- बद्रीनाथ के संबंध में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी। उस समय महालक्ष्मी ने बदरी यानी बेर का पेड़ बनकर भगवान विष्णु को छाया दी थी और खराब मौसम में रक्षा की थी। लक्ष्मी जी के इस समर्पण से भगवान प्रसन्न हुए थे और उन्होंने इस जगह को बद्रीनाथ नाम से प्रसिद्ध होने का वर दिया था। बद्रीनाथ धाम में विष्णुजी की एक मीटर ऊंची काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। ये मंदिर करीब 3100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।

केमिकल से पके आम हैं नुकसानदेह

मीठा रसीला आम खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उतने ही इसके फायदे भी हैं। पेड़ पर पका आम सबसे टेस्टी और हेल्दी माना जाता है, लेकिन बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने के लिए कुछ दुकानदार कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायनों का इस्तेमाल करके आमों को जल्दी पकाते हैं। केमिकल्ज से पके आम खाने से सेहत को कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं। इससे आपको उल्टी, दस्त, कभी-कभी खून के साथ दस्त, अत्यधिक कमजोरी, छाती में दर्द, एसिडिटी और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, इससे त्वचा पर अल्सर होने, आंखों को नुकसान होने, गला खराब होने और निगलने में कठिनाई आदि का भी रिस्क है। आइए जानते हैं क्यों नहीं खाने चाहिए केमिकल से पके आम।

केमिकल वाले आम खाने से दिक्कतें

केमिकल्ज से पके आम खाने से खांसी, घाव और घरघराहट जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। अगर आम खाने के तुरंत बाद सांस लेने में दिक्कत हो तो देर नहीं करनी चाहिए और डाक्टर से मिलना चाहिए।

हाइपोक्सिया का भी रिस्क

हाइपोक्सिया रासायनिक रूप से पके आम खाने का एक आम दुष्प्रभाव है। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें टिश्यू तक पर्याप्त आक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और यह ज्यादातर तब होता है जब रक्त में आक्सीजन का स्तर गिर जाता है।

आम पकाने में किन केमिकल्ज का इस्तेमाल होता है

आमों को जल्दी पकाने के लिए कई तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें एथिलीन गैस, कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटिलीन गैस और इथेफोन शामिल हैं। आम को सही समय से पहले पकाया जाता है या पकाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए गलत केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसे आम खाने में सुरक्षित नहीं होते।

आम की पहचान कैसे करें

आम खरीदते समय ध्यान दें कि आम पर कहीं सफेद या ग्रे रंग का पाउडर तो नहीं लगा है। अगर ऐसा पाउडर दिखे तो समझ लें कि ये आम केमिकल से पकाए गए हैं।

आम का रंग देखें

आम की किस्म के हिसाब से रंग अलग हो सकता है। लेकिन अगर रंग में कुछ गड़बड़ लगे तो ये केमिकल से पका हुआ हो सकता है। कभी-कभी केमिकल से पकाए आमों पर हरे धब्बे भी रह जाते हैं, जो प्राकृतिक नहीं लगते। ये धब्बे पीले रंग से आसानी से अलग दिखाई देंगे।

दबाकर चैक करें

पके और मीठे आम की पहचान करने के लिए उसे खरीदते समय हल्का सा दबाकर देखें। आम अगर सॉफ्ट लगे तो ये पके हुए आम की पहचान है, लेकिन अगर आम दबाने पर सख्त महसूस हो, तो हो सकता है आम केमिकल से पकाया हुआ है। चखने में भी केमिकल से पकाए आमों का पता चल सकता है। इन्हें खाने के बाद मुंह में हल्की जलन हो सकती है। पके आम की महक मीठी होने की संभावना होती है। कभी-कभी उनके तनों पर फलों जैसी सुगंध आती है। आपको तने के सिरे के पास जांच करनी चाहिए, वहां गंध अधिक तीव्र होनी चाहिए। पके आम का रस आसानी से निकल सकता है।

महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से दूर होता है अकाल मृत्यु का भय, दूर होते हैं सभी कष्ट

अनन्या मिश्रा

महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में इस मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस मंत्र के जप से मनुष्य के ऊपर से सभी तरह की बाधाएं और परेशानियों का अंत हो जाता है।

महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में इस मंत्र का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भयमुक्त और रोगमुक्त जीवन चाहता है और अकाल मृत्यु के डर से खुद को दूर रखना चाहता है, उसको भगवान शिव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र है। इस मंत्र के जप से मनुष्य के ऊपर से सभी तरह की बाधाएं और परेशानियों का अंत हो जाता है।

महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है कि हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उनके तीन नेत्र हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह से फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, ठीक उसी तरह हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं।

कैसे करें जप

महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना जप करने से व्यक्ति को कई लाभ होते हैं। रोजाना सूर्योदय से पहले रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि इस मंत्र का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है। शिवपुराण के मुताबिक महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करने से जातक को अधिक लाभ प्राप्त होता है।

महामृत्युंजय मंत्र के फायदे

महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से भगवान शंकर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और व्यक्ति को धन-धान्य की कमी नहीं होती है।

इस मंत्र के रोजाना जप से रोगों का नाश होता है और मनुष्य हमेशा निरोगी रहता है।

महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है।

जो भी व्यक्ति धन-संपत्ति की इच्छा रखता है, उसको इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए।

मालीवाल के केस में दिल्ली पुलिस आई एक्शन में...

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए की स्वाति करतूत को लेकर संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना की स्वीकारोक्ति के बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस के पीसीआर रिकार्ड मे पेंडिंग चल रही स्वाति मालीवाल की टेलीफोनी कंपलेंट पर गुरूवार को स्वाति मालीवाल के नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गई। तीन की संख्ध्या में दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों ने तकरीबन 2- 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के मसले का पुलिस ने कोई खुलासा नही किया है। इस बीच मीडिया खबर के मुताबिक आरोपी मालीवाल ने जिस पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, वह गुरूवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ कार में लखनऊ पहुंचा हुआ है। कथित आरोपी विभव कुमार केजरीवाल के साथ कार में बैठे दिखाई दिए तो मीडिया ने उनसे केस के बारे में पूछने की कोशिश की । लेकिन विभव कुमार कार का शीशा तक नहीं खोला। साथ ही जुबान पर ताले लगा लिए। संवाददाता विभव से शीशा खोलने की रिक्वेस्ट करते रहे पर मजाल है कि उन्होने नजर तक उपर उठाई हो। दरअसल विभव कुमार ,अरविंद केजरीवाल के शुरू से करीबी रहा हैं।

दरअसल साल 2000 में केजरीवाल और मनीष सिसौदिया ने परिवर्तन नाम से एनजीओ बनाया था। 2006 में वहीं एनजीओ पब्लिक कॉज रिफार्म्स फांउडेशन के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। ये एनजीओ अरविंद केजरीवाल ने मैग्भसेसे पुरस्कार के पैसों से बनाया था। तब इन दोनों एनजीओ की सर्वेसर्वा स्वाति मालीवाल थी ।केजरीवाल इसका नाम था तो चेहरा स्वाति थी। इसके बाद मनीष सिसौदिया ने 2012 में कबीर नाम से एक एनजीओ बनाया ।कबीर कॉज फांउडेशन का बेबी था ।विभव कुमार इस एनजीओ में स्टाफ था। तब स्वाती मालीवाल इसकी बॉस थी। विभव इसके नीचे काम देखता था। ऐसे में स्वाति को सीएम हाऊस में केजरीवाल से मिलने से रोकना स्वाति के बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसी बात से बिदकी मालीवाल ने विभव कुमार को बोला। लेकिन विभव अंदर जाने से मना कर दिया। उनमें आपस में गर्मा गर्मी हो गई और बात मारने पीटने तक आ पहुंची । इसी मारपीट और दुर्व्यवहार को लेकर मालीवाल ने पुलिस पीसीआर को फोन कर दिया। इसके अलावा कंपलेंट लिखवाने के लिए बाकायदा मालीवाल सिविल लाइन थाने जा पहुंची और मौखिक रूप से विभव द्वारा मारपीट ओर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। लेकिन घटना के तीन दिन बाद भी लिखित कंपलेंट नही दी। इसबीच संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम आवास में हुई घटना को सरेआम कर दिया। इस सरेआम स्वीकारोक्ति के बाद दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान ले लिया और स्वाति मालीवाल के घर पहुंच कर घटना की जानकारी ली। लेकिन पुलिस ने अबतक कोई खुलासा नहीं किया है। कहा जा रहा है कि संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बखेड़ हो गया है। संजय सिंह से पार्टी में पूछा जा रहा है कि आपने किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सारा मामला स्वाति मालीवाल से सांसदी से इस्तीफा मांगने मांगना भारी पड गया है। दरअसल केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को स्वाति की जगह पर राज्यसभा सांसद बनाने की कवायद है। और स्वाति मालीवाल को एडजस्ट करने की बात चल रही है। बता दें कि गुरूवार 16 मई के अंक में इस बात का खुलासा किया गया था। जो धीरे धीरे सामने आगे आने लगा है। अब देखना ये है कि स्वाति मालीवाल को अब क्रिकेटर हरभजन सिंह की जगह एडजस्ट करने की बात सामने आ रही है।

स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में FIR दर्ज, CM अरविंद केजरीवाल के PA का नाम शामिल

स्वाति ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने कहा था कि वह उनके बयान के आधार पर FIR दर्ज करेगी। बता दें एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर स्वाति के साथ बदसलूकी मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा था। वहीं एनसीडब्ल्यू ने बिभव कुमार को नोटिस भी भेजा है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार का नाम शामिल किया गया है। बता दें, इससे पहले पुलिस ने स्वाति के आवास पर जाकर उनका बयान दर्ज कराया था। करीब 4 घंटे तक चली पूछताछ में स्वाति ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने कहा था कि वह उनके बयान के आधार पर FIR दर्ज करेगी। बता दें, एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर स्वाति के साथ बदसलूकी मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा था। वहीं एनसीडब्ल्यू ने बिभव कुमार को नोटिस भी भेजा है।

स्वाति ने तोड़ी चुप्पी

इससे पहले स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर तीन दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा-मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं।

बीजेपी राजनीति न करे: स्वाति

उन्होंने कहा- जिन लोगों ने चरित्र हनन करने की कोशिश की, ये बोला की दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल ज़रूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। BJP वालों से ख़ास गुज़ारिश है इस घटना पे राजनीति न करें।

4,600 से अधिक स्कूलों के लिए हैं पांच बम निरोधक दस्ते, विस्फोटक का पता

दिल्ली के 4600 से अधिक स्कूलों के लिए पांच बम निरोधक दस्ते तैनात हैं और बम का पता लगाने वाली 18 टीमें मौजूद है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष दाखिल स्थिति रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए पिछले साल दिशा-निर्देश जारी किए थे और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश भी दिया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों पर बम हमलों के खतरे से जुड़ी याचिका पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है। पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली के 4,600 से अधिक स्कूलों के लिए कुल पांच बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) और बम का पता लगाने वाली 18 टीमें हैं।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष दाखिल स्थिति रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए पिछले साल दिशा-निर्देश जारी किए थे और बम की धमकी के मामले में बीडीएस की तैनाती के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश भी जारी किया गया है।

स्कूलों में 120 मॉक ड्रिल आयोजित

यह भी सूचित किया कि एक जनवरी 2023 से छह मई के बीच स्कूलों में 120 मॉक ड्रिल आयोजित की गईं। याचिकाकर्ता अर्पित भार्गव की याचिका पर पुलिस ने यह भी बताया कि एक-एक बीडीएस मध्य, पूर्व, नई दिल्ली और दक्षिण रेंज में स्थित है। इनमें क्रमशः 1764, 1032, 76, 1762 स्कूल हैं।

इसमें कहा गया है कि बम निरोधक दस्तों और बम का पता लगाने वाली टीमों के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया 2021 में पहले ही जारी की जा चुकी है।

खतरे से निपटने के लिए कई टीमें तैनात

दिशानिर्देशों के अनुसार खतरे की कॉल का आकलन करने के बाद स्थानीय पुलिस न केवल स्थान पर पहुंचेगी, बल्कि स्थिति से निपटने के लिए बीडीटी, अग्निशमन विभाग, यातायात पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम के साथ-साथ एम्बुलेंस और अस्पतालों को भी शामिल करेगी।

दिल्ली से बीते दो दिन में 18 उड़ानें हुईं रद्द, कई देरी से रवाना; सामने आई ये बड़ी वजह

परिवहन विशेष न्यूज

बीते लगातार दो दिनों से नई दिल्ली से संचालित होने वाली 18 उड़ानें रद्द हुई। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया स्पाइसजेट इंडिगो की उड़ानें शामिल रहीं। न सिर्फ उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को दिक्कत हुई बल्कि कई उड़ानों के तय समय से विलंब से पहुंचने के कारण भी यात्रियों को तकलीफों से दो चार होना पड़ा। एयरलाइंस कंपनियों ने इसकी वजह भी बताई।

नई दिल्ली। बीते लगातार दो दिनों से नई दिल्ली से संचालित होने वाली 18 उड़ानें रद्द हुई। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो की उड़ानें शामिल रहीं। न सिर्फ उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को दिक्कत हुई, बल्कि कई उड़ानों के तय समय से विलंब से पहुंचने के कारण भी यात्रियों को तकलीफों से दो चार होना पड़ा। इनमें सर्वाधिक परेशानी विदेश से आने वाली उड़ानों के यात्रियों को उठाना पड़ा। जिन्हें यहां कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, उनकी फ्लाइट छूट गई।

ऐसे में कई यात्री नई व्यवस्था होने तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। यात्रियों ने अपनी परेशानियों को एक्स पर साझा करते हुए संबंधित एयरलाइंस से मदद की गुहार लगाते हुए इस पूरे प्रकरण पर नाराजगी जताई। दिल्ली एयरपोर्ट की साइट के मुताबिक एयर इंडिया की चेन्नई, अहमदाबाद, वड़ोदरा, ग्वालियर व एअर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर, श्रीनगर, गोवा की दो उड़ानें संचालित नहीं हुई। उधर इंडिगो ने भी गुवाहाटी, रायपुर की उड़ानें रद्द की। स्पाइसजेट ने गोवा, कांडला, दरभंगा और गुवाहाटी की उड़ानें रद्द की। विस्तारा ने मुंबई जाने वाली उड़ान संचालित नहीं की।

यात्री और उनके स्वजन दोनों रहे परेशान

एक्स पर सचिन शर्मा नामक यूजर ने स्पाइसजेट की गुवाहाटी जाने वाली उड़ान के रद्द होने पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि अगर आपको विमान संचालित ही नहीं करना है तो आप बुकिंग ही क्यों करते हैं? पहले आपने उड़ान के समय को लगातार विलंबित किया और अंत में उसे रद्द कर दिया।

साहिल नामक यूजर ने एक्स पर एयर इंडिया को टैग करते हुए लिखा कि उनके माता पिता शिकागो की 21 घंटे की लंबी उड़ान के बाद नई दिल्ली पहुंचे। यहां से उन्हें वडोदरा की यात्रा करनी थी, लेकिन अचानक वडोदरा की उड़ान को रद्द कर दिया गया। मेरे माता-पिता की उम्र करीब 65 वर्ष है। वे एयरपोर्ट पर करीब 12 घंटे से फंसे हैं। उनकी मदद की जाए।

मदद के नाम पर केवल रिफ्रेशमेंट दिया गया

बतौर साहिल उनके माता पिता को होटल तक मुहैया नहीं कराया गया। उन्हें मदद के नाम पर केवल रिफ्रेशमेंट दिया गया है। वे परेशान हैं। साहिल के पोस्ट पर आइजीआई एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी एजेंसी डायल ने संज्ञान लिया और अपने कर्मियों को साहिल के माता पिता की मदद के लिए भेजा। बाद में इस पूरे प्रकरण पर साहिल ने डायल को धन्यवाद ज्ञापित किया लेकिन उनके माता-पिता एयरपोर्ट पर फंसे रहे, इस बारे में किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

सेन फ्रांसिस्को से दिल्ली पहुंचे यात्री को हुई परशानी

वहीं नंदिनी नामक यूजर ने अपने पोस्ट में कहा कि उनके माता पिता सेन फ्रांसिस्को से नई दिल्ली पहुंचे, यहां से उन्हें चेन्नई जाना था। लेकिन उनकी फ्लाइट केवल इसलिए मिस हो गई क्योंकि सेन फ्रांसिस्को से ही उनकी उड़ान यहां विलंब से पहुंची।

नंदिनी का कहना है कि उनके माता पिता 10 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, लेकिन एयर इंडिया ने उनकी मदद नहीं की। रियास नामक यूजर ने एयरपोर्ट की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट वाले कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं। इसका कारण केवल और केवल उड़ानों का विलंबित होना है। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

ऑपरेशन से जुड़े कारणों की वजह से उड़ानें रद्द

इस पूरे प्रकरण पर एयर इंडिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की रद उड़ानों के बारे में एयरलाइंस का कहना है कि ऐसा ऑपरेशन से जुड़े कारणों की वजह से हुआ है। हमने यात्रियों को उड़ानों के रद होने के बारे में पूर्व सूचना दे दी थी।

CUET परीक्षा में फिर बदहाली, 15 घंटे पहले तक बदलते रहे सेंटर; कई छात्रों के छूटे एग्जाम

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से बृहस्पतिवार को राजधानी दिल्ली में 200 से अधिक केंद्रों पर कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) आयोजित की गई। दो साल होने के बावजूद परीक्षा में बदहाली देखने को मिली। सर्वाधिक परेशानी परीक्षा केंद्रों को तय करने में हुई। विद्यार्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले देर शाम तक अपने केंद्रों के बारे में जानकारी मिल सकी।

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से बृहस्पतिवार को राजधानी दिल्ली में 200 से अधिक केंद्रों पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) आयोजित की गई। दो साल होने के बावजूद परीक्षा में बदहाली देखने को मिली। सर्वाधिक परेशानी परीक्षा केंद्रों को तय करने में हुई।

विद्यार्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले देर शाम तक अपने केंद्रों के बारे में जानकारी मिल सकी। इससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। कुछ छात्रों ने इंटरनेट मीडिया पर परीक्षा छूटने की बात भी लिखी है। परीक्षा के इंतजामों से अभिभावक भी नाराज दिखाई दिए।

परीक्षा केंद्र को लेकर स्पष्टता की कमी

सीयूईटी के लिए दिल्ली के हंसराज कॉलेज को केंद्र बनाया गया था। यहां परीक्षा देने आए छात्र गौरव ने बताया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन, परीक्षा केंद्र को लेकर स्पष्टता की कमी थी। एक दिन पहले तक उन्हें नहीं पता था कि केंद्र कहां होगा।

बेटे को गुरुग्राम से परीक्षा दिलाने पहुंची मां कुसुम ने बताया कि परीक्षा केंद्र तय करने के लिए एनटीए को नीति बनानी चाहिए। शाम सात बजे के बाद उन्हें केंद्र के बारे में सही जानकारी मिल सकी। इससे पहले दो बार संदेश और आए थे। इसमें केंद्र के नाम दूसरे थे। बार-बार बेटे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाना पड़ रहा था। इससे काफी दुविधा की स्थिति बनी रही। देर शाम केंद्र की स्थिति साफ हुई।

केंद्रों को लेकर स्थित स्पष्ट होनी चाहिए

द्वारका सेक्टर पांच स्थिति केंद्रीय विद्यालय में बेटे को परीक्षा दिलाने आए द्वारका के महावीर एनक्लेव में रहने वाले इंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि दो बार बेटे की परीक्षा का केंद्र बदल चुका है। परीक्षा से एक रात पहले शाम सात बजे पता कि अब केंद्र बदल गए हैं तभी हम जल्दीबाजी में जाकर पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। कई जगह प्रिंट आउट निकलने में परेशानी होती है। केंद्रों को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

पूर्वी दिल्ली में कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल में परीक्षा देनी आई छात्रा रश्मि ने बताया कि केंद्र की जानकारी एक दिन पहले देर शाम मिली है। काफी दूर रखे गए हैं। इससे छात्रों को परेशानी हुई। हालांकि, स्कूल ने प्रवेश में ढील दी है, इससे थोड़ी राहत है।

देरी से परीक्षा शुरू होने पर दिखाई नाराजगी

कालका जी स्थित राजकीय सह शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीयूईटी की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली परीक्षा 12 बजे शुरू हुई। इसके बाद एक बजे शुरू होने वाली परीक्षा आधा घंटा देरी से शुरू हुई। शास्त्री नगर के रहने वाले संतोष शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्र एक दिन पहले बदलने से उनको काफी दिक्कत हुई है और वह अपने दस्तावेजों की फोटो कापी भी नहीं करा सके।

हरियाणा के रोहतक के मोखरा गांव से परीक्षा देने आए प्रवेश ने बताया कि उनका केंद्र दो बार बदला गया। परीक्षा देने के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ा। प्रेम नगर के अभिषेक ने बताया कि एक घंटा देरी से परीक्षा शुरू हुई। इससे उनको काफी दिक्कत हुई। विद्यालय के गेट पर परीक्षा शुरू होने से दो मिनट पहले ही रोल नंबर की सूची लगाई गई, जिससे वहां अफरातफरी का माहौल रहा।

दूर केंद्र से परेशान थे अभिभावक, सुविधाएं बढ़ाने की मांग

छात्रों को सीयूईटी परीक्षा दिलाने पहुंचे अभिभावक केंद्रों की दूरी को लेकर परेशान थे। बेटे को परीक्षा दिलाने हंसराज कालेज पहुंचे दिलीप ने बताया कि परीक्षा केंद्र घर से नजदीक बनाया जाना चाहिए। वे पूर्वी दिल्ली से आए हैं। पूर्वी दिल्ली में कई केंद्र बनाए गए हैं। कई अभिभावक हरियाणा से आए हैं। एनटीए को इस समस्या का सामधान निकालना चाहिए।

कला निकेतन स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने भी अधिक दूर केंद्र किए जाने की शिकायत की। उन्होंने केंद्र दूर है और उसके बाहर खड़े रहने की सुविधा नहीं है। अगर पेड़ है तो उसके नीचे खड़े हो जाओ, नहीं तो धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। केंद्रों के बाहर व्यवस्था होनी चाहिए।

ऑफलाइन परीक्षा होने से छात्रों को रही राहत

एनटीए की ओर से 15 विषयों की परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की गई। इससे छात्रों को तकनीकी समस्या से निजात मिली। पिछले दो सालों से पूरी परीक्षा ऑनलाइन मोड पर हो रही थी। तकनीकी समस्या आने और सर्वर न चलने से छात्र परीक्षा से वंचित रह जाते थे। ऑफलाइन परीक्षा पर छात्रों ने संतोष जताया।

स्टेशनरी, वर्दी का पैसा छात्रों के बजाय प्रिंसिपलों के पास रखने पर विचार करे एमसीडी: दिल्ली हाईकोर्ट

एमसीडी ने कहा कि मौजूदा नीति के अनुसार इन उद्देश्यों के लिए छात्रों के खातों में पैसा स्थानांतरित किया जाता है। यह भी कहा कि वह एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए बैंक खाते खोलने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है और अदालत को उन छात्रों का डेटा दिया गया है जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं।

नईदिल्ली। किताबें और वर्दी देने के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को शैक्षिक सामग्री, वर्दी और पाठ्यपुस्तकों की खरीद के लिए छात्रों के बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने की अपनी नीति बदलने और इसके बजाय इसे प्रिंसिपल के खाते में रखने का सुझाव दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने पूछा कि यह राशि संबंधित स्कूल प्रिंसिपल या शिक्षकों के बैंक खातों में क्यों नहीं रखी जा सकती, जिसका उपयोग छात्रों के लिए इन वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है। एमसीडी ने कहा कि मौजूदा नीति के अनुसार इन उद्देश्यों के लिए छात्रों के खातों में पैसा स्थानांतरित किया जाता है। यह भी कहा कि वह एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए बैंक खाते खोलने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है और अदालत को उन छात्रों का डेटा दिया गया है जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं।

10 मई से गर्मियों की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद

एमसीडी ने कहा कि शुरुआत में राशि प्रिंसिपल के खाते में भेजी जाती है और बाद में छात्रों के खातों में भेज दी जाती है। हालांकि एमसीडी स्कूल 10 मई से गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश जारी किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान से पाठ्यपुस्तकें समय पर एकत्र की जाएं और 31 मई तक छात्रों को बुलाकर वितरित की जाएं।

नकद राशि उनके बैंक खातों में स्थानांतरित

एनसीडी ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि एमसीडी का लक्ष्य 15 जून या उससे पहले सभी शेष छात्रों के लिए बैंक खाते खोलना है ताकि नोटबुक और स्टेशनरी की खरीद के लिए नकद राशि उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जा सके। इस पर पीठ ने एमसीडी को एक जुलाई तक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई चार जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

दुश्मनों के मंसूबों को जड़ से नष्ट करेगी डिजिटल फोरेंसिक लैब, सीमा पार से आनेवाले ड्रोन का हो सकेगा खात्मा

इन ड्रोन को एंटी राग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी (आरओजीयूई) की ओर से तुरंत मारकर नष्ट कर दिया जाता है। उसमें रडार और जैमर डिटेक्शन में दिक्कत आती है और उसका डाटा भी रिकवर नहीं हो पाता जिस वजह से दुश्मन के मंसूबों तक आखिर वह ड्रोन उसने क्यों भेजा गया उसका पता नहीं लग पाता। साइबर फोरेंसिक लैब नष्ट डिवाइस से भी डाटा रिकवर

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। डिजिटल क्रांति नित नए अध्याय लिख रही है। उसी के माध्यम से आतंकी संगठनों के मंसूबों को भी पस्त किया जा रहा है। एक कड़ी आगे बढ़ते हुए आतंकी देशों द्वारा देश की सीमा पर भेजे जाने वाले ड्रोन के मकसद का भी पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब तैयार हो रही है। दुश्मन देश लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर आए दिन ड्रोन के माध्यम से कभी हथियार गिराते हैं तो कभी नशे का सामान फेंकते हैं या फिर रेकी करते हैं।

इन ड्रोन को एंटी राग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी (आरओजीयूई) की ओर से तुरंत मारकर नष्ट कर दिया जाता है। उसमें रडार और जैमर डिटेक्शन में दिक्कत आती है और उसका डाटा भी रिकवर नहीं हो पाता, जिस वजह से दुश्मन के मंसूबों तक आखिर वह ड्रोन उसने क्यों भेजा गया, उसका पता नहीं लग पाता। एक माह बाद शुरू होने वाली साइबर फोरेंसिक लैब नष्ट डिवाइस से भी डाटा रिकवर कर सारे जवाब उगलवा लेगी।

स्वीडन-इजरायल साइबर टूल का इस्तेमाल

नोएडा स्थित गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में तैयार इस डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब में डाटा रिकवर करने के लिए स्वीडन-इजरायल साइबर टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें डाटा स्ट्रैक्शन टूल को लगाया जाएगा, जिसमें ड्रोन की नष्ट चिप को लगाया जाएगा, इसके बाद उसकी सारी वह जानकारी हासिल होनी शुरू हो जाएगी। इसमें उसकी रिपोर्ट किसके पास है, किस स्थान से उड़ाया गया, ड्रोन के द्वारा कहां-कहां की तस्वीरें क्लिक की गईं, कहां भेजी गईं सब राज उगले जाएंगे। डाटा स्ट्रैक्शन वो टूल है, जिसमें नष्ट डाटा खुद ही रिकवर हो जाता है। इसी तरह किसी आतंकी या देश के विरुद्ध साजिश रचने वाले किसी आरोपित का नष्ट किया हुआ मोबाइल, लैपटाप मिलता है तो उसे भी रिकवर किया जा सकेगा। इसके लिए स्वीडन, इजरायल, अमेरिका के साइबर टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें नष्ट गैजेट के कुछ अंश को डालने के बाद में मैसेज, ई-मेल, फोटो, फाइल समेत अन्य जानकारी हासिल हो सकेंगी।

लगातार बढ़ रहे ड्रोन हमले

ड्रोन साइबर लैब गौतमबुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. निशाकांत ओझा के मार्गदर्शन में मुंबई स्थित साइबर टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार होने के अंतिम चरण में है। कंपनी और यूनिवर्सिटी

के बीच अनुबंध प्रक्रिया भी हो चुकी है। जून माह के अंत तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। साइबर एवं एयरोस्पेस सिक्योरिटीज (प्रतिरोध-आतंकवाद-एआइ) विशेषज्ञ डॉ. निशाकांत ओझा ने बताया कि वर्ष 2020 से 2023 के बीच आंकड़ों को देखा जाए तो 500 से अधिक प्रतिबंधित ड्रोन के जरिये देश के बार्डर क्षत्र गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू में वेपन हिरोइन, ओपीएम (अफीम), नाइन एमएम पिस्टल, 132 राउंड गन भेजी गई हैं। पिछले वर्षों की तुलना में अब ड्रोन गतिविधि तीन गुना बढ़ गई हैं। इन गतिविधियों को रोकने के मकसद से ही इस लैब को तैयार किया गया है।

आत्मघाती ड्रोन का डाटा भी होगा रिकवर

इस लैब की एक और खासियत है कि इसमें दुश्मन देश से भेजे जाने वाले आत्मघाती ड्रोन का डाटा भी रिकवर किया जा सकेगा। इसमें ड्रोन के मलबे को एकत्र करके लैब लाया जाएगा और इसके बाद डाटा रिकवर किया जाएगा। यह ड्रोन इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से लैस होते हैं। ये बिलकुल मानव बम की तरह काम करते हैं यानी अपना मकसद पूरा करने के बाद खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं। ऐसे ड्रोन का डाटा डिटेक्ट करना अभी तक बड़ी चुनौती बना हुआ था। इससे निपटने के लिए यह लैब कारगर साबित होगी।

हर सुरक्षा एजेंसी के लिए मददगार

इस लैब में न केवल ड्रोन का ही डाटा रिकवर होगा बल्कि टूटे हुए मोबाइल फोन, लैपटाप इत्यादि का भी डाटा रिकवर हो सकेगा। इससे सभी ला इंफोर्समेंट एजेंसी, एनआइए, रा, सीबीआइ, आइबी, ईडी, स्टेट पुलिस, एसटीएफ, एसओजी को लाभ होगा। इससे इन एजेंसियों को किसी भी आपराधिक घटना या आतंकवादी घटना का पर्दाफाश करने में काफी मदद मिलेगी।

किस बार्डर पर कितने ड्रोन मिले

बार्डर एरिया	ड्रोन संख्या
गुजरात	30
जम्मू	50
पंजाब	380
राजस्थान	40

(नोट : वर्ष 2020 से 2023 के बीच बीएसएफ की ओर से कार्रवाई में डैमेज ड्रोन का आंकड़ा)

रूस, इजरायल, स्वीडन जैसे देश आज इसी प्रकार के सेंटर संचालित कर रहे हैं। नोएडा का सेंटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) के रूप में संचालित होगा। हमारे देश में तमाम आतंकी गतिविधियां होती हैं, जिसमें फोन इस कदर डैमेज मिलता है, जिससे डाटा रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे फोन व ड्रोन का डाटा रिकवर करने का काम अब आसानी से किया जा सकेगा। - प्रोफेसर डॉ निशाकांत

पलायन' घर पर लिखे इस शब्द का रहस्य कर देगा हैरान, इसके पीछे छिपी हैं कई परिवारों की 'सिसकियां'

गाजियाबाद के मसूरी इलाके में कुछ लोग अपने घरों के बाहर पलायन के पर्चे लगाने को मजबूर हैं। यह पर्चे उन परिवारों के दर्द की सिसकियां भी बयान करते हैं। यहां रहने वाले इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों से इतने परेशान हो गए कि उन्हें यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला।

गाजियाबाद। गाजियाबाद के मसूरी के आकाश नगर में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन शब्द लिखे पर्चे चस्पा कर दिए हैं।

आरोप है कि उनके घर के आसपास रात के वक्त कुछ युवक आते हैं, जो शराब पीकर गाली-गलौज करते हैं। विरोध करने पर धमकी देते हैं।

इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई लेकिन आरोपित अपनी हरकत से बाज नहीं आए, ऐसे में माहौल खराब हो रहा है।

एसीपी से मिलने गए लोग तो...

लोगों का कहना है कि इस मामले की शिकायत करने के लिए वह एसीपी मसूरी नरेश कुमार के कार्यालय में गए, वहां पर उन्होंने अभद्रता की और कार्यालय से बाहर निकलने के लिए कह दिया। जिसका वीडियो भी लोगों ने बनाया है।

'पुलिस ने मेरे भाई को छोड़ने के लिए मांगे 5 लाख', नोएडा पुलिस चौकी में सुसाइड मामले में पीड़ित पक्ष का दावा; पूरा स्टाफ निलंबित

बिसरख कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चिपियाना पुलिस चौकी में पुलिस हिरासत में अलीगढ़ के युवक योगेश की मौत हो गई। उसने आत्महत्या की है। उसका शव गमछे से बंधा हुआ पंखे से लटका मिला है। योगेश के भाई जितेंद्र ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रताड़ना से उसके भाई की जान गई है। आरोप है कि उसके भाई को छोड़ने के एवज में पुलिस ने पांच लाख रुपये मांगे थे।

ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चिपियाना पुलिस चौकी में पुलिस हिरासत में अलीगढ़ के युवक योगेश की मौत हो गई। उसने आत्महत्या की है। उसका शव गमछे से बंधा हुआ पंखे से लटका मिला है।

योगेश के भाई जितेंद्र ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रताड़ना से उसके भाई की जान गई है। आरोप है कि उसके भाई को छोड़ने के एवज में पुलिस ने पांच लाख रुपये मांगे थे। पचास हजार उसने दे दिए थे। एक हजार रुपये शराब के भी दिए। वहीं पुलिस ने किया दावा किया है कि समाज में बदनामी के डर से युवक ने आत्महत्या की है। उसके खिलाफ महिला सहकर्मी ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस योगेश को उठाकर पूछताछ के लिए चौकी लाई थी।

पुलिसकर्मियों के खिलाफ बिसरख कोतवाली में मामला दर्ज

पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने चौकी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ बिसरख कोतवाली में केस दर्ज किया गया है।

चिपियाना पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा युवक योगेश को बुधवार दोपहर घर से उठाकर लाया गया

था। उस पर आरोप था कि उसने किसी महिला सहकर्मी से दुष्कर्म किया।

योगेश एक बेकरी की दुकान में नौकरी करता था। वह किचन का पूरा काम देखता था। करीब 15 कर्मचारियों की निगरानी उसके जिम्मे थी। मामले में एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।

परिवार ने लगाया ये आरोप

प्रसारित हुए वीडियो में स्वजन ने आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत में पूरी रात योगेश को रखा गया। उनको उससे मिलने नहीं दिया गया। युवक के साथ मारपीट की गई।

पुलिसवालों ने पांच लाख की रिश्वत मांगी, जिसमें से पचास हजार रुपये उसने दे दिए थे। एक हजार रुपये शराब के भी दिए थे।

बुधवार रात रिश्वत की रकम लेने के बाद पुलिसकर्मियों ने कहा कि जो रकम बकाया रह गई है वह सुबह लेकर आना और अपने भाई को ले जाना।

पीड़ित का आरोप है कि वह सुबह अपने भाई को लेने चौकी पर पहुंचा तो उसका भाई उसे मृत अवस्था में मिला। मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी गई है।

एसीपी व कोतवाल का स्पष्टीकरण तलब

मामले में एसीपी हेमंत उपाध्याय व बिसरख कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। दोनों की भूमिका के संबंध में तीन दिन के अंदर जांच रिपोर्ट तैयार कर पुलिस आयुक्त को सौंपी जाएगी। मामले की जांच एडीसीपी नोएडा मनीष मिश्रा करेंगे।

दो बार पूछताछ के लिए लाया गया

स्वजन का आरोप है कि योगेश को बुधवार दोपहर पुलिस पूछताछ के लिए उठाकर लाई। कुछ देर बाद उसको छोड़ दिया गया। रात होने पर पुलिस उसे दोबारा पूछताछ के लिए उठा लाई।

अलीगढ़ के खैर का रहने वाला था योगेश

योगेश मूल रूप से अलीगढ़ के खैर के गांव अमरगढ़ी का रहने वाला था। वर्तमान में वह ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चिपियाना क्षेत्र में रहता था। वह नामी कंपनी की बेकरी में ड्यूटी करता था। करीब चार सालों से वह नौकरी कर रहा था। मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। स्वजन की तहरीर के आधार पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।-सुनीति, डीसीपी सेंट्रल नोएडा

भारत में गरीबी उन्मूलन पर पूर्व में गम्भीरता से ध्यान ही नहीं दिया गया

प्रह्लाद सबनानी

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ष 2014 में लागू किया गया जिसके माध्यम से आम नागरिकों के बैंकों में बचत खाते खोले गए, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, धन के प्रेषण की सुविधा, बीमा तथा पेंशन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

भारत में हाल ही के वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में आई भारी कमी के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विकसित देशों के कई वित्तीय एवं आर्थिक संस्थानों ने भारत की आर्थिक नीतियों की मुक्त कंठ से सराहना की है। यह सब दरअसल भारत में तेज गति से हुए वित्तीय समावेशन के चलते सम्भव हुआ है। याद करें वर्ष 1947, जब देश ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय देश की अधिकतम आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर थी। जबकि, भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था। परंतु, पहिले अरब से आक्रांताओं एवं बाद में अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा तथा देश के नागरिकों को गरीबी की ओर धकेल दिया। भारत में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत से 'गरीबी हटाओ' के नारे तो बहुत लगे परंतु, गरीबी नहीं हटी। 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ राजनैतिक दलों ने कई बार सता हासिल की किंतु देश से गरीबी हटाने के गम्भीर प्रयास शायद कभी नहीं हुए और गरीब वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा।

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ष 2014 में लागू किया गया जिसके माध्यम से आम नागरिकों के बैंकों में बचत खाते खोले गए, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, धन के प्रेषण की सुविधा, बीमा तथा पेंशन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज मिलता है, हालांकि बचत खाते में कोई न्यूनतम राशि रखना आवश्यक नहीं है। एक लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। साथ ही, इस योजना के माध्यम से दो लाख रुपए का जीवन बीमा उस लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों पर मिलता है।

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (Direct Benefit Transfer Scheme) को भी लागू किया गया जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गरीब वर्ग के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि को सीधे ही हितग्राहियों के बचत खातों में जमा कर दिया जाता है। इससे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 100 प्रतिशत लाभ की राशि सीधे ही उनके हाथों में पहुंच जाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत, वर्ष 2013 के बाद से 31 मार्च 2022 तक, 24.8 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे ही लाभार्थियों के बचत खातों में जमा की जा चुकी है, इसमें अकेले वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही 6.3 लाख करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के बचत खातों में हस्तांतरित की गई थी। वर्ष 2014 के पूर्व तक जब इन लाभार्थियों के बचत खाते विभिन्न बैंकों में नहीं खुले थे तब तक कांग्रेस एवं अन्य सरकारों के शासनकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि सामान्यतः नकद राशि के रूप में इन लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती थी।

आपको शायद ध्यान होगा कि एक बार देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि के एक रुपए में से केवल 16 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंच पाते हैं। शेष 84 पैसे इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र की जेब में पहुंच जाते है। अब आप स्वयं आंकलन करें कि यदि बैंक में 50 करोड़ लाभार्थियों के बचत खाते नहीं खुले होते और यदि उक्त वर्णित केवल 8 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को नकद राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती तो इन लाभार्थियों के पास केवल 4 लाख करोड़ रुपए की राशि ही पहुंच पाती एवं शेष 21 लाख करोड़ रुपए की राशि इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र के पास ही रह जाती। अब आप आगे एक और कल्पना कर लीजिये कि पिछले 70 वर्षों के दौरान कितनी भारी भरकम राशि इन गरीब हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाई होगी। इस राशि का आकार शायद आपकी कल्पना से भी परे है। सहायता की यह राशि यदि गरीबों तक पहुंच गई होती तो शायद हो सकता है कि देश से अभी तक गरीबी भी दूर हो चुकी होती। अब जब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत सहायता की राशि हितग्राहियों के खातों में सीधे ही पहुंच रही है तो देश से गरीबी भी तेजी से कम होती दिखाई दे रही है, जिसकी तारीफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्त कंठ से हो रही है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकों के माध्यम से इस दृष्टि से बहुत ठोस कार्य किया गया है। न केवल 50 करोड़ से अधिक बचत खाते विभिन्न भारतीय बैंकों में खोले गए हैं बल्कि आज इन बचत खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जमा हो गई है और बचत की यह भारी भरकम राशि बैंकों द्वारा देश के आर्थिक विकास में उपयोग की जा रही है। इस प्रकार, भारत का गरीब वर्ग भी इन बैंक खातों के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त 50 करोड़ से अधिक बचत खातों में 50 प्रतिशत खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, अर्थात अब भारतीय महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं सहित, भी आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं।

भारी मात्रा में खोले गए इन बचत खातों के माध्यम से गरीब वर्ग के नागरिकों का बैंकिंग सम्बंधी इतिहास भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, जिससे इस वर्ग के नागरिकों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में आसानी होने लगी है। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से लागू की जा रही विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं का लाभ भी अब गरीब वर्ग को मिलने लगा है। कोरोना महामारी के तुरंत बाद जब देश में स्थितियां सामान्य बनने की ओर अग्रसर हो रहीं थीं तब केंद्र सरकार ने खोमचा वाले, रेहड़ी वाले एवं ठेलों पर अपना सामान बेचकर छोटे छोटे व्यवसाईयों द्वारा अपना व्यापार पुनः प्रारम्भ करने के उद्देश्य से एक विशेष ऋण योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अंतर्गत उक्त वर्णित छोटे छोटे व्यवसाईयों को बैंक द्वारा आसानी से ऋण प्रदान किया गया था क्योंकि इस वर्ग के नागरिकों के पूर्व में ही बैंकों में बचत खाते खुले हुए थे। बैंकों द्वारा यह ऋण बगैर किसी व्यक्तिगत गारंटी के प्रदान किया गया था। और, हजारों की संख्या में छोटे छोटे व्यवसाईयों ने निर्धारित समय सीमा में इस ऋण को अदा कर, पुनः बढ़ी हुई राशि के ऋण बैंकों से लिए थे और अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाया था। बैंकों में खोले गए बचत खातों से गरीब वर्ग को इस प्रकार के लाभ भी हुए हैं।

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के हर गरीब नागरिक को वित्तीय मुख्य धारा से जोड़ा है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीबतम व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिला है। आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी भारत के 50 प्रतिशत नागरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात बैंकों से नहीं जुड़े थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी भारी मात्रा में

आपको शायद ध्यान होगा कि एक बार देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि के एक रुपए में से केवल 16 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंच पाते हैं। शेष 84 पैसे इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र की जेब में पहुंच जाते है। अब आप स्वयं आंकलन करें कि यदि बैंक में 50 करोड़ लाभार्थियों के बचत खाते नहीं खुले होते और यदि उक्त वर्णित केवल 8 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को नकद राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती तो इन लाभार्थियों के पास केवल 4 लाख करोड़ रुपए की राशि ही पहुंच पाती एवं शेष 21 लाख करोड़ रुपए की राशि इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र के पास ही रह जाती।

नागरिकों ने उठाया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 15.99 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 49 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा केवल 436 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 33.78 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 48 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा केवल 20 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। अटल पेंशन योजना से 5.20 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 40.83 करोड़ नागरिकों को ऋण प्रदान किया गया है

प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने प्रारम्भिक समय से ही वित्तीय समावेशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खातों में से लगभग 67 प्रतिशत बचत खाते ग्रामीण एवं अर्धशहरी केंद्रों पर खोले गए हैं, जिसे मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खाताधारकों को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है। यह रूपे कार्ड उपयोगकर्ता द्वारा समस्त एटीएम, पोस टर्मिनल एवं ई-कामर्स वेबसाइट पर लेनदेन करने की दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2016 में 15.78 करोड़ बचत खाताधारकों को रूपे कार्ड प्रदान किया गया था एवं अप्रेल 2023 तक यह संख्या बचकर 33.5 करोड़ तक पहुंच गई है।

सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक

कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के मामले में कौन बेहतर ? जानें डिटेल्स

परिवहन विशेष न्यूज

2024 Maruti Suzuki Swift को पांच वेरिएंट - LXi VXi ZXi ZXi प्लस और ZXI प्लस DT में पेश किया गया है जिनकी कीमत 6.49 लाख रुपये से लेकर 9.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है। Citroen C3 की बात करें तो इसे लाइव फील शाइन और शाइन डीटी में 6.2 लाख रुपये से 9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की कीमतों के साथ सेल किया जाता है।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में भारतीय बाजार में अगली पीढ़ी की मारुति सुजुकी स्विफ्ट लॉन्च की है। चौथी पीढ़ी की स्विफ्ट नई डिजाइन, इंजन और फीचर्स के साथ पेश की गई है। इंडिययन मार्केट में ये हैचबैक Citroen C3 को कंपीट करने वाली है। आइए, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं।

वेरिएंट और कीमत

2024 Maruti Suzuki Swift को पांच वेरिएंट - LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस और ZXI प्लस DT में पेश किया गया है, जिनकी कीमत 6.49 लाख रुपये से लेकर 9.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है।

Citroen C3 की बात करें तो इसे लाइव, फील, शाइन और शाइन डीटी में 6.2 लाख रुपये से 9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की कीमतों के साथ सेल किया जाता है।

डिजाइन और डायमेंशन

अपडेटेड Swift की लंबाई 3860 मिमी, चौड़ाई 1735 मिमी, ऊंचाई 1520 मिमी और व्हीलबेस 2450 मिमी है। वहीं, Citroen C3 की लंबाई 3981 मिमी, चौड़ाई 1733 मिमी और ऊंचाई 1604 मिमी है और इसका व्हीलबेस 2540 मिमी है। डिजाइन के मामले में दोनों गाड़ियां एक-दूसरे से काफी अलग हैं।

इंजन और परफॉरमेंस

नई स्विफ्ट एक बिल्कुल नए जेड-सीरीज, 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है, जो 82 hp की शक्ति और 112 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। गियरबॉक्स विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी शामिल है।

नई स्विफ्ट ने MT वेरिएंट के लिए 24.8 kmpl और AMT के लिए 25.75 kmpl की फ्यूल एफिशियंशी का दावा किया है।

Citroen C3 को दो इंजन विकल्पों में पेश किया गया है। इसमें एक 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है और दूसरा 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल यूनिट।

टोयोटा कर रही हाइलक्स ईवी की टेस्टिंग, थाइलैंड में जल्द शुरू हो सकता है प्रोडक्शन

टोयोटा मोटर की ओर से नए बैटरी-इलेक्ट्रिक हाइलेक्स पिकअप ट्रक की टेस्टिंग की जा रही है। कंपनी अलग-अलग सड़क और तापमान स्थितियों में कई उपयोग के मामलों के लिए हाइलेक्स बीईवी का परीक्षण कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हाइब्रिड बिक्री बढ़ेगी। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। टोयोटा मोटर विभिन्न परिस्थितियों में इसके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए नए बैटरी-इलेक्ट्रिक हाइलेक्स पिकअप ट्रक की टेस्टिंग कर रही है। कार निर्माता 2025 के अंत तक थाईलैंड में वाहन का निर्माण करने की तैयारी कर रहा है।

हाइलेक्स बीईवी को लेकर क्या अपडेट ?

टोयोटा मोटर एशिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रसाद गणेश ने बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहन का जिक्र करते हुए फ्यूचर मोबिलिटी एशिया शिखर सम्मेलन के मौके पर रॉयटर्स को बताया, ₹हमारा इरादा यहां हाइलेक्स बीईवी का उत्पादन करने का है।₹ गणेश ने हाइलेक्स बीईवी के मूल्य निर्धारण या उत्पादन मात्रा के बारे में विवरण देने से इनकार कर दिया, जो टोयोटा की पहली ईवी पिकअप ट्रक पेशकश होगी।

थाई सरकार ने मार्च में कहा था कि प्रतिद्वंद्वी जापानी वाहन निर्माता इसुजु मोटर्स भी थाईलैंड में अपने इलेक्ट्रिक डी-मैक्स पिकअप ट्रक का निर्माण करने की योजना बना रही है। वाहन का लक्ष्य मुख्य रूप से थाई घरेलू बाजार होगा, लेकिन गणेश ने कहा कि वाहन निर्माता हाइलेक्स बीईवी के निर्यात पर भी विचार करेगा।

टेस्टिंग जारी

टोयोटा अलग-अलग सड़क और तापमान स्थितियों में कई उपयोग के मामलों के लिए हाइलेक्स बीईवी का परीक्षण कर रही है। गणेश ने कहा, ₹मुझे इस पर जितनी अधिक रेंज लगानी होगी, उतनी ही अधिक बैटरी लगानी होगी, जिसका मतलब है कि वाहन का वजन भी काफी भारी हो जाता है, जिसका मतलब है कि लोडिंग बहुत कम हो सकती है।

टोयोटा ने मारी बाजी

ईवी उद्योग के लीडर्स में टेस्ला और चीन की बीवाईडी को पीछे छोड़ते हुए, टोयोटा को हाइब्रिड वाहनों की बढ़ती मांग से लाभ हुआ है, क्योंकि अधिक उपभोक्ता कंपनी की पारंपरिक ताकत पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड को अपना रहे हैं। गणेश ने कहा कि टोयोटा को उम्मीद है कि थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हाइब्रिड बिक्री बढ़ेगी।

भरी गर्मी में करनी है कूल ड्राइविंग, तो घर से निकलते समय इन बातों का रखें ध्यान

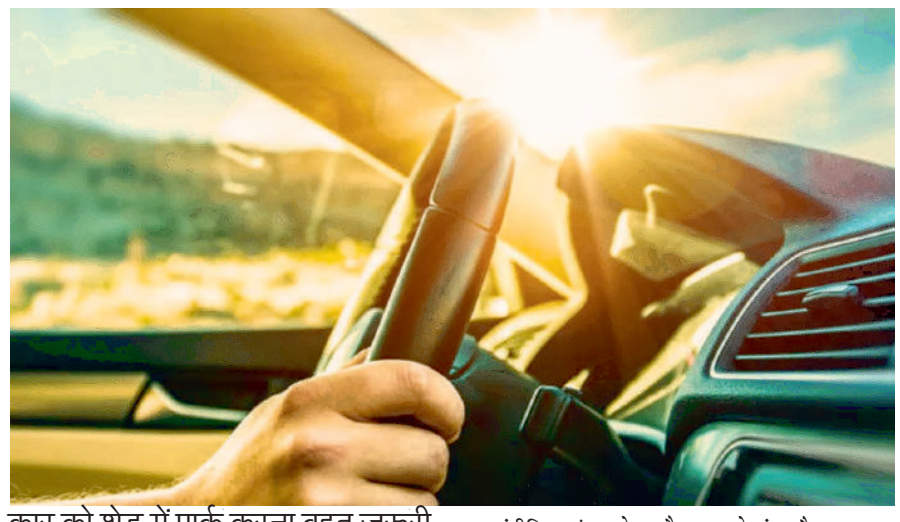

कार को शेड में पार्क करना बहुत जरूरी है। खासकर जब हम ड्राइविंग पर निकले उससे 2-3 घंटे पहले तक गाड़ी छांव में पार्क रहनी चाहिए। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कार ड्राइविंग शुरू करने से पहले ट्रैफिक रूट जरूर चेक करें। अलग-अलग रास्ता देखें और ऐसा रूट चुनें जिसमें आप बिना ट्रैफिक से जल्दी पहुंच जाएं। आइए कुछ जरूरी टिप्स के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। गर्मियों के मौसम में ट्रैवल करना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि, जिनके पास खुद का वाहन है, उन्हें थोड़ी राहत रहती है। मौजूदा समय में कार ड्राइविंग शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक चीजों का ध्यान रखना काफी जरूरी है। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।

गाड़ी छांव में पार्क करें

कार को शेड में पार्क करना बहुत जरूरी है। खासकर जब हम ड्राइविंग पर निकले उससे 2-3 घंटे पहले तक गाड़ी छांव में पार्क रहनी चाहिए। इससे कार का इंटीरियर ठंडा रहेगा और आपको अंदर बैठकर क्लाइमेट कंट्रोल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।

हाइड्रेशन का ध्यान रखें

कार में जाने से पहले ये देखें कि आपके पास पर्याप्त पीने का पानी है या फिर नहीं ? अगर आपने पानी नहीं रखा है, तो उसे साथ ले लें। कई बार हम यात्रा के दौरान हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं और फिर वो बीमारी का कारण बन जाता है। पानी के अलावा आप ORS जैसे पेय पदार्थ भी अपने साथ रह सकते हैं।

ट्रैफिक रूट चेक करें

अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कार ड्राइविंग शुरू करने से पहले ट्रैफिक रूट जरूर चेक करें। अलग-अलग रास्ता देखें और ऐसा रूट चुनें जिसमें आप बिना ट्रैफिक से जल्दी पहुंच जाएं। ऐसा करने से आपकी ट्रिप शॉर्ट होगी और गाड़ी को भी जल्दी आराम मिलेगा। मौसम विभाग ने लू को लेकर जारी किया अलर्ट, जानें क्या है Heat wave और कैसे करें इससे अपना बचाव

टायर प्रेशर जाचें

गर्मियों के मौसम में टायर खराब होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में हमेशा नई ट्रिप शुरू करने से पहले गाड़ी के सभी टायरों की जांच करें और टायर प्रेशर को भी मेंटेन करके रखें। ऐसा करने से आपको बीच रास्ते में रुकने जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

फ्रांस में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बेहतर तरीके से चलाती हैं कार

यूरोप के एक बड़े देश France में इन दिनों Drive Like Woman कैंपेन को काफी जोर-शोर से चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के जरिए देश भर में पुरुषों से महिलाओं की तरह कार चलाने करने की अपील की जा रही है। यूरोपीय देश फ्रांस में पुरुषों से इस तरह की अपील क्यों की जा रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। यूरोप के देश फ्रांस में इन दिनों एक खास तरह के कैंपेन को चलाया जा रहा है, जिसके जरिए देशभर के पुरुषों से अपील की जा रही है कि वह महिलाओं की तरह कार को चलाएं। फ्रांस में ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

France में चल रहा Drive Like Woman कैंपेन

दुनियाभर में रोजाना बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। जिनमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग घायल भी होते हैं। इसे कम करने के लिए यूरोप के एक बड़े देश France में खास तरह के कैंपेन को चलाया जा रहा है। इस कैंपेन को Drive Like Woman नाम दिया गया है। जिसके जरिए देश के पुरुषों से अपील की जा रही है कि वह महिलाओं की तरह ही वाहन को चलाएं।

क्यों की जा रही है अपील

देश में कार के कारण होने वाले सड़क हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देशभर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में जिम्मेदार सबसे ज्यादा पुरुष हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाएं काफी कम संख्या में हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में हादसों को कम करने के लिए इस तरह के कैंपेन को शुरू किया गया है। इस कैंपेन के तहत देश में कई जगहों पर होर्डिंग भी लगाए गए हैं।

संस्था ने जारी की रिपोर्ट

फ्रांस की रोड सेफ्टी ऑब्जर्वेट्री संस्था की ओर से एक रिपोर्ट को जारी किया गया है। जिसके मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में जितने भी भयानक सड़क हादसे हुए हैं, उनके लिए 84 फीसदी पुरुष जिम्मेदार हैं। शराब पीकर वाहन चलाने के कारण हुए हादसों में पुरुषों की जिम्मेदारी 93 फीसदी तक है।

क्यों होते हैं हादसे

दरअसल, फ्रांस में ज्यादातर पुरुष खुद को नोटिस करवाने के लिए और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए वाहनों को काफी तेज स्पीड में चलाते हैं। जिससे कई बार कार पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और हादसा हो जाता है। वहीं महिलाएं एक निश्चित स्पीड और यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाती हैं, जिससे हादसों में उनकी भागीदारी काफी कम रहती है।

मोदी की मुसलमानों से आत्ममंथन करने की अपील

अवधेश कुमार

नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि वे अपने व्यवहार पर आत्ममंथन करें। प्रधानमंत्री अगर लोकसभा चुनाव के बीच देश के दूसरे सबसे बड़े समुदाय से ऐसी अपील करते हैं तो इसे निश्चय ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विरोधी कह रहे हैं कि हार के डर से घबराकर मोदी ने परोक्ष रूप से मुसलमानों से वोट देने की अपील की है। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के भारतीय मुसलमानों पर दिए गए वक्तव्य को किस रूप में देखा जाए?

यह सच है, जैसा प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि मैंने पहले कभी इन विषयों पर बातचीत नहीं की। मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा आरोप भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी पर ही लगाए गए। अपने मुख्यमंत्रित्वकाल के आरंभ में अवश्य उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की लेकिन बदलाव न दिखने पर इस विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। यह भी सच है कि उन्होंने पहली बार मुसलमानों से आत्ममंथन करने को कहा है।

उन्होंने कहा कि आप यदि यह सोचते रहेंगे कि सत्ता में किसे बिठाएंगे और किसे उतारेंगे, उससे अपने बच्चों का भविष्य ही खराब करेंगे। कोई चाहे इसे किस रूप में भी देखे, स्वतंत्रता के बाद से पहले कांग्रेस और बाद में ज्यादातर पार्टियों ने वोट के लिए मुसलमानों के बीच जनमत को विकृत किया। दुर्भाग्य से मुसलमान समाज के पढ़े-लिखे लोगों में से बड़े वर्ग ने कभी इसका मूल्यांकन नहीं किया कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस और उसके बाद अन्य कई पार्टियों ने उनके अंदर डर पैदा कर वोट तो लिया, पर उनके उत्थान, वास्तविक कल्याण या विकास के लिए जो करना चाहिए, वह नहीं किया गया। ऐसे-ऐसे मुद्दे पार्टियों और सरकारों ने उठाए और उन पर काम किया, जो भावनात्मक रूप से उनको छूते थे या उनके समाज में यथास्थिति को बनाए रखने वाले थे, जो उनके सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास में बाधक थे और मजहबी रूप से सच नहीं।

इस चुनाव में भी लगभग यही हो रहा है। मुसलमानों के अंदर यह भय पैदा किया जा चुका है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में लौटी तो भारत में इस्लाम के लिए कयामत आ जाएगी, उनकी लाखों मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, उनको नमाज पढने तक से वंचित किया जाएगा तथा वे अपनी इच्छा अनुसार इस्लामी मजहब का पालन भी नहीं कर सकेंगे। यह पहला चुनाव है जहां मुसलमानों के अगुवा माने जाने वाले व्यक्तियों के बड़े समूह ने भाजपा को वोट न देने को दीन और ईमान का विषय बना दिया है। फिर, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम विरोधी होने के आरोप पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि न हम इस्लाम के विरोधी हैं न मुसलमान के। हमारा यह काम ही नहीं है। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि मुसलमान इस पर विचार करें कि सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ उन्हें कांग्रेस के शासनकाल में क्यों नहीं मिला? अगर लाभ मिला होता तो सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद के नियंत्रण और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चलने वाली यू.पी.ए. सरकार को सच्चर समिति के माध्यम से मुसलमानों के हर क्षेत्र में पिछड़े होने की रिपोर्ट सामने नहीं लानी पड़ती। हालांकि सच्चर रिपोर्ट अतिवाद से भरी थी तथा तथ्यों के नाम से सामने रखे गए अनेक ङ्कषबदू विचारों और कल्पनाओं वाले थे। बावजूद, उस समय तक की सरकारों ने मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया।

भारतीय मुसलमानों के अगुवा वर्ग की एप्रोच सही होती तो उनकी मानसिकता बदलती और नरेंद्र मोदी सरकार दुश्मन नहीं नजर आती। इस सरकार के कार्यकाल में पंथ, मजहब, जाति या रंग के आधार पर सरकारी नीतियों में किसी तरह के भेदभाव का एक भी प्रमाण नहीं है। सच यह है कि भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं की तुलना में आबादी के प्रतिशत से ज्यादा लाभ सरकार की योजनाओं का मिला है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है। यह बदलाव सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन आदि देशों में साफ दिखाई पड़ता है। खाड़ी के देशों में योग की ओर मुसलमानों का आकर्षण है लेकिन भारतीय मुसलमानों ने योग को ही इस्लाम विरुद्ध मान लिया। सऊदी अरब में योग सरकारी सिलेबस का विषय है। शरीयत के अनुसार चलने वाले शासन के मुल्कों में भी अनेक ऐसे हैं, जिन्होंने तीन तलाक को गैर-इस्लामी घोषित किया हुआ है। अनुच्छेद 370 का इस्लाम से क्या लेना-देना था? जम्मू-कश्मीर तो छोड़िए, देश भर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इसे लेकर छाती पीट रहा है। गो हत्या निषेध मुसलमान के विरुद्ध कदम कैसे हो गया? समान नागरिक संहिता में किसी मजहबी कर्मकांड पर रोक नहीं है। लंबे समय से मुसलमानों के दिमाग में बिठा दिया गया कि समान नागरिक संहिता इस्लाम के विरुद्ध है।

इस तरह के नैरेटिव से मुस्लिम समाज को बाहर आने की आवश्यकता है। क्या प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद ऐसा लगता है कि भारतीय मुसलमान आत्ममंथन करेंगे और उन्हें वोट के रूप में देखने वाली पार्टियां ऐसा करने देंगी? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बताते हैं कि राजीव गांधी के शासनकाल में शाहबानो मामले पर जब उन्होंने स्टैंड लिया तो उसे सही मानते हुए भी उन्हें कहा गया कि अगर एक समाज गटर में रहना चाहता है तो तुम अपनी राजनीतिक बलि क्यों चढ़ाना चाहते हो। शाहबानो पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को राजीव गांधी सरकार द्वारा पलटना मुस्लिम तुष्टीकरण का शर्मनाक उदाहरण था।

मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि हमारे देश के बेईमान और पाखंडी नेताओं ने वोट के लिए सीधी एप्रोच यही बनाई कि उनके समाज के दोषों को दूर करने या उन्हें मुख्यधारा में लाने की जगह जहां जैसे हैं, वैसे ही छोड़ दो और उनके हितैषी होने का प्रदर्शन करते रहो। बस रोजा के समय बड़ी इफ्तार पार्टियां दे दो, बड़े मुस्लिम चेहरों द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल हो जाओ, सिर पर टोपी या गमछा डालकर नमाज अदा करने का नाटक करो आदि। क्या कभी मुसलमानों ने सोचा है कि इस तरह के व्यवहार से उन्हें क्या प्राप्त हुआ? कोई आपके लिए इफ्तार पार्टी न दे, आपके साथ नमाज अदा करने का नाटक न करे, आपकी टोपी न पहने लेकिन आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, गरीब मुसलमानों को उचित आवास दे, उनके घरों में बिजली और पानी पहुंचाए, मदरसों का उन्नयन कर इस्लामी शिक्षा के साथ उनमें आज के दौर के अनुरूप पाठ्यक्रम और इसके लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करे, इस्लाम के नाम पर गलत प्रथा से मुक्ति का कानून बनाए तो क्या उसे मुस्लिम विरोधी सरकार कहा जाएगा? इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील और कही गई बातों पर मुस्लिम समुदाय को सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हालांकि राजनीति के कारण देश का वातावरण ऐसा नहीं है, जिसमें तत्काल इसका बहुत ज्यादा सकारात्मक असर होगा।

नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि वे अपने व्यवहार पर आत्ममंथन करें। प्रधानमंत्री अगर लोकसभा चुनाव के बीच देश के दूसरे सबसे बड़े समुदाय से ऐसी अपील करते हैं तो इसे निश्चय ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विरोधी कह रहे हैं कि हार के डर...

संपादक की कलम से

जख्मों पर चुनावी नमक

हिमाचल ने चुनाव के बहाने अपने मुद्दे चुनने शुरू किए हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि धरती के लिए जनता के सरोकार गहरा असर रखते हैं। केंद्रीय विषयों से हटकर यहां टक्कर उन कसौटियों की है, जहां सरकारों को अपने प्रदर्शन के घाव भरने हैं। यानी चुनाव के एक पहलू में मोदी तो दूसरे में सुक्खू सरकार है, फिर भी बयानों के तीर चल रहे हैं तूफानों के बीच। यह दीगर है कि मीडिया कुरेद रहा है विकास के जख्मों में फंसे उन मुद्दों को जहां जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं कर पाए। अंततः सरकारों की प्राथमिकता में हलके छोटे-बड़े साबित हो रहे हैं। चुंबक दौड़ रहे हैं ताकि राजनीतिक धुरवों पर भीड़ एकत्रित हो, लेकिन जनता की सुनवाई में चुनाव की गवाही मंजूर होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं। ऊपरी सतह पर ये चुनाव मुद्दाविहीन सरीखी परिस्थिति में हैं, लेकिन भीतरी तौर पर अलग-अलग तहों में सुगबुगाहट है। कांग्रेस उपचुनावों को बिकाऊ माल की तरह देख रही है, तो भाजपा का सारा कर्मकांड वहीं लगा है। यह दीगर है कि कुछ स्थानीय मुद्दे उपचुनावों पर भारी हैं, लेकिन हर अंदाज में कोई न कोई सरगना इनके आगे खड़ा है। चुनाव की भाषा में मर्यादा पीछे छूट गई है और मतदान की फिरौती में उसूल बिक रहे हैं। पहली बार कुछ हस्तियों का चुनावी दर्पण के सामने खड़ा होना भी मुद्दा है। कंगना की जीत हार में जयराम ठाकुर मुद्दा हैं, तो कांगड़ा के श्रृंगार में हिमाचल सरकार मुद्दा है। हमीरपुर में अनुराग की हस्ती को विराम लगाने की हर कोशिश में सरकार का रुतबा उपचुनावों की कलम से लिखा जाएगा, तो सुजानपुर के आसमान को लांघने की मशक्कत में कहां दो जमा दो का गणित बचा है। इस बार चुनावों में अनेकों मुकद्दमे और अनेकों गवाहियां मशक्कत कर रही हैं। इसलिए मुद्दों में मुकद्दमों की पैरवी है ही कहां। ये छह उपचुनाव बारह हस्तियों के बीच भाजपा और कांग्रेस की हस्ती का मजमून हैं, तो कहीं पूरे घटनाक्रम में सरकार के ओहदे और ओहदेदारों को भी घसीट रहा है। इसीलिए ताज्जुब नहीं कि मुद्दों के बजाय सियासी दुश्मनी के मोर्चों पर फैसलों की ताकीद की जा रही है। जनता किसे पसंद करे, किसके बजट पर भरोसा करे। आरोप को माने या प्रत्यारोप को कोसें।

हर कोई अपनी बांसुरी बजा रहा है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बयानों की कदमताल न जानी और न ही पहचानी जा सकती है। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिली सशर्त जमानत को घसीट कर लोकतंत्र के मायनों से ऊपर चुनाव देख रहे हैं या कांगड़ा की हस्ती में निरापद होने की संज्ञा खोज रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने प्रयास की खोज में आनंद शर्मा को कांगड़ा ले आए, तो शांता कुमार की फिजाओं का गठजोड़ राजीव भारद्वाज के नाम हो गया। शायद जनता के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के अपरिहार्य अध्याय भी फट चुके हैं। उसे हर चुनाव एक नया दृष्टांत लगता है। वह उम्मीदवारों की जीत में हारने की हस्ती बन चुकी है। छह उपचुनावों का संग्रह उसकी संपत्ति कदापि नहीं, फिर भी इस कुश्ती में उड़ रही धूल उसे देखने नहीं दे रही। जनता को भी मालूम है कि मुद्दे अब चलते नहीं या मुद्दों पर राजनीति चल नहीं सकती, इसलिए वह वोट देने की मशीन की तरह व्यवहार कर रही है। वह वोट बैंक के सोच में अपने मन के खातों में हिसाब लगा रही है। यानी गारंटियों के मार्फत सोचेगी तो ओपीएस उसे विश्वास दिलाएगी, लेकिन मुफ्तखोरी में केंद्र के राशन-मोदी के भाषण पर भरोसा करेगी तो भाजपा की संगठनात्मक ताकत का बिल्ला सीने पर लगाएगी। विचित्र परिस्थितियों और विचित्र समाधानों के चुनावों में क्या जनता अपनी हस्ती के अनुरूप मतदान कर पाएगी, यह भी एक सवाल है जो मुद्दों से इतर न जाने क्या खोज रहा है।

राय

जीत और दस किलो अनाज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लिख कर दे रहे हैं कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस पद पर नहीं रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े का दावा है कि भाजपा 200 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस हद तक बयान दे रहे हैं कि भाजपा 140 सीटों को भी तरस जाएगी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एवं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आकलन है कि भाजपा 195 सीटों तक सिमट जाएगी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पहले ही अपना गणित बता चुके हैं कि भाजपा 220-230 सीटें ही जीत सकती है। विपक्ष के ऐसे दावों की हुंकार भरी जा रही है और वह लगातार देश को आश्वस्त करने में जुटा है कि उसने एक आंतरिक सर्वे कराया है, जिसके मुताबिक 'इंडिया' गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीत रहा है, लिहाजा अगली सरकार 'इंडिया' की ही बनेगी। खडग़े ने लखनऊ प्रेस वार्ता के दौरान यह वायदा भी किया कि यदि 'इंडिया' की सरकार बनी, तो 80 करोड़ से अधिक उन गरीबों को 10 किलोग्राम अनाज प्रति माह मुफ्त दिया जाएगा, जिन्हें अभी 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है।

सरकारी खजाने पर 2 लाख करोड़ रुपए की सबसिडी का बोझ पहले से ही है, लिहाजा 10 किलो अनाज बांटने पर वह दोगुनी हो जाएगी। दिलचस्प है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह नया जुमला उछाला है, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली की जनसभाओं में इस योजना पर सवाल उठाते हुए जनता से पूछा है कि आपको रोजगार चाहिए या 5 किलो मुफ्त अनाज'? राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता भी इस योजना पर सवाल उठाते रहे हैं कि क्या 80 करोड़ से अधिक भारतीय इतने गरीब हैं कि यदि उन्हें मुफ्त अनाज न मिले, तो वे भूखों मर सकते हैं? इस योजना के 10 किलो तक विस्तार पर कांग्रेस में रणनीतिक विरोधाभास क्यों हैं? क्या नेतागण आपस में विमर्श नहीं करते? कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र भी इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश है, लिहाजा कई कांग्रेसी खडग़े की घोषणा से हैरान भी होंगे! कांग्रेस अध्यक्ष ने, सपा अध्यक्ष की मौजूदगी में, नए वायदे की घोषणा तब की है, जब चार चरणों में 378 लोकसभा सीटों पर मतदान सम्पन्न हो चुका है और 164 सीटों पर मतदान ही शेष है। 70 फीसदी से अधिक जनादेश तय होकर ईवीएम में दर्ज हो चुका है। जिन 164 सीटों पर मतदान अभी शेष है, 2019 के चुनाव में उनमें से 97 सीटें भाजपा ने जीत कर हासिल की थीं। इस बार के आम चुनाव में अब विपक्ष के भीतर ऐसा कौनसा 'सुपर विश्वास' जाग उठा है कि उसने जीत के दावों की बौछार कर दी है। कई बार तो विपक्ष के दावों पर थोड़ा-सा यकीन भी होने लगता है, लेकिन देश के गृहमंत्री अमित शाह का दावा भी कौंधने लगता है कि जिन सीटों पर मतदान हो चुका है, उनमें से 270 सीटें मोदी जीत चुके हैं। यानी बहुमत भाजपा-एनडीए के पक्ष में मिल चुका है। दोनों पक्षों के दावों को छोड़ भी दिया जाए, तो यह भी नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष ने ऐसे दावे 2019 में भी किए थे। ऐसे आंतरिक सर्वे की बात राहुल गांधी तब भी दोहराया करते थे। मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, चोर चौकीदार नहीं रहेगा, यह तो कांग्रेस का चुनावी जुमला बन गया था। नतीजा पूरा देश जानता है। यदि अब भी आगामी चरणों में भाजपा की 50 फीसदी सीटें भी कम हो जाएं, तब भी वह 319 सीटें जीत सकती है। यदि भाजपा की जीत में 10 फीसदी सीटें ही कम हों, तो भी वह 357 सीटें जीत सकती है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने इस बार 328 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं, लिहाजा 300 से अधिक सीटें जीतने का 'इंडिया' का दावा सवालिया लगता है।

सादा जीवन, उच्च विचार की लंगोटी!

वे मेरे पास 'सादा जीवन-उच्च विचार' की लंगोटी लेकर आए और बोले-'शर्मा तुम इसे पहन लो, अब यह मेरे कोई काम नहीं आ रही। बच्चे कहते हैं, इस युग में यह अपने घर में अच्छी नहीं लगती। तुम तो खुद सिद्धान्तवादी हो, इसे पहन लोगे तो पक्के उसूलवादी बन जाओगे। मेरे यहां तो यह बीस वर्षों से खूंटी पर टंगी गंदी हो गई है। किसी बढिया डिटर्जेंट से धोकर पहन लेना, सच्चे आदर्शवादी बन जाओगे।' मैंने कहा-'श्यामलाल जी, कोठी, बंगला, कार और नौकर-चाकर वाले हो गए तो तुम्हारे लिए यह सादा जीवन-उच्च विचार की लंगोटी अप्रासंगिक हो गई। मैं आपकी इस लंगोटी का क्या करूंगा। मैंने तो ऑलरेडी पहले से ही पहन रखी है और इसी से मेरा जीवनयापन हो रहा है, वरना पांच-सात हजार के वेतन से मेरे बंटता क्या है? उसूलों से और सादगी से रहता हूं तो गुजारा हो जाता है, वरना भूखों मरने की नौबत है।' श्यामलाल जी जिद पर अड़े थे, बोले-'तुम एक और लंगोटी पहन लो, गुजारा और आसान हो जाएगा। मैं इसे फेंक भी नहीं सकता। विचार का अपमान मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चे एमएनसी में लगे हुए हैं, मैं पार्षद हूं। अच्छा कमा लेते हैं, अब सादा जीवन-उच्च विचार को हमारे यहां पूछने वाला कोई है नहीं। पोते-पोती कान्वेंट में पढ़ते हैं। पीजा-बर्गर और चाकलेट का सादा जीवन से कोई मेल नहीं। उच्च विचार जबसे राजनीति में आया हूं, तब से बेमानी हो गए हैं, इसलिए भैया मुझे इस बोझ से हल्का तुम ही कर सकते हो। अभी तुम इस बोझ को लादे हुए हो, इसलिए थोड़ा सा वजन और सही। घर इसे लेकर जाऊंगा तो इसकी बहुत बुरी गत होगी।'

तभी मेरी पत्नी आ गई, वह आकर बोली-'श्यामालाल जी आज कैसे हम गरीबों के आना हुआ? और घर में सब ठीक-ठाक तो हैं न?' श्यामलाल जी बोले-'घर में तो सब ठीक हैं भाभी, यह सादा जीवन-उच्च विचार की लंगोटी शर्मा जी को देने आया था, परन्तु ये भी ना-नुकर कर रहे हैं। तुम्हीं समझाओ न, ये इसे भी पहन लें।' पत्नी ने कहा-'शर्मा जी ने तो भैया, पहले से ही पहन रखी है और इसी से काम चल रहा है। मेरा कहा मानो तो दिखाने और वोटर को धोखा देने के लिए आप पहन लो। आजकल बड़े आदमियों की जीवन शैली यही है। अंदर से अलग और बाहर कुछ और। हमने तो इसे आदर्श मानकर अपना रखा है, आपके चुनाव में काम आएगी।' 'उसके लिए तो भाभी मेरे पास हजार पैंतरे और बहाने हैं। वे काम आते हैं। चुनाव आजकल इससे नहीं जीता जाता। वोटर को भी प्रलोभन देकर उसका वोट हासिल किया जाता है। हम राजनेताओं के चेहरे एक नहीं, अनेक हैं, वर्ना हमें जीने कौन दे? काजल की कोठरी में रहते-रहते पूरे काले हो गए हैं। पचास भला-बुरा सुनते हैं, तब राजनीति से कमाकर खाते हैं।' श्यामलाल जी बोले, तो पत्नी ने कहा-'हमें मत समझाओ श्यामलाल जी, हम आज की राजनीति और राजनेताओं को भली प्रकार से जानते हैं। जीवन में कुछ भला भी करो। इस धिक्कारपूर्ण छल-कपट के कोटर से बाहर निकलकर भी देखो। आदमी दो रोटी ही खाता है, नोट नहीं।'

पूरन सरमा

विचार

घटिया खेल सामग्री खरीदना बंद करें

इस स्तर पर अगर हिमाचल प्रदेश में घटिया खेल सामान न खरीद कर उच्च क्वालिटी का खेल सामान खरीदा होगा तो स्तरीय खेल सुविधा होगी व जो खिलाड़ी प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव में खेल छोड़ देते हैं, वे अपने घर में रह कर खेल जारी रख सकते हैं। घटिया खेल सामान की खरीद बंद हो'

खेल केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं है, अपितु यह किसी भी देश के गौरव व उस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। शिक्षा नीति खेलों को किनारे रख कर नहीं बनाई जा सकती है। स्वास्थ्य के मुख्य घटक स्पीड, स्ट्रैंथ, लचक व इडोरैंस को विकसित करने का सही समय बालक के पांच वर्ष से लेकर वयस्क होने तक का होता है। इसलिए शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए असली खेल सामग्री जरूरी है। खेलों में आज उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खेल उपकरणों से लेकर कृत्रिम प्ले फील्ड तक में काफी सुधार किया जा रहा है। अच्छे खेल परिणामों के लिए खेल सामान की क्वालिटी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, मगर खेल सामान की खरीददारी में बहुत बड़ा गोलमाल है। इस विषय पर पहले भी कई बार इस कॉलम के माध्यम से लिखा जा चुका है, मगर अभी तक इसमें कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश के जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के कार्यालयों व शिक्षा संस्थानों में हर वर्ष करोड़ों रुपए का खेल सामान जैम व अन्य माध्यमों से खेल विभाग व शिक्षा निदेशालय खरीद कर आगे देता है, जो बेहद निम्न दर्जे का होता है।

विभागों व शिक्षा संस्थानों को चाहिए कि वे घटिया खेल सामग्री की खरीद पर लगाम लगा कर अच्छी क्वालिटी का खेल सामान प्रदेश के विद्यार्थी खिलाडियों को दिलाएं, ताकि हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज खेलों का स्तर बहुत ही ऊपर उठ चुका है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर खिलाड़ी पूरे विश्व में अपने देश का डंका बजा रहे हैं। इस अद्भुत खेल प्रदर्शन के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों व प्रतिभाशाली खिलाडियों के साथ-साथ उनके पास स्तरीय खेल किट व उच्च तकनीकी के खेल उपकरणों का होना भी बहुत ही जरूरी होता है। चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए आज प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर कई प्रकार के उपकरण विकसित हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार खेल जगत में भी आज के अति मानवीय खेल परिणामों में विकसित प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर बनाई गई आधुनिक खेल सामग्री का विशेष योगदान है। जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इनसान को फिट रहने के लिए किसी न किसी खेल का सहारा लेना पड़ता है।

ऐसे में जब लाखों नहीं करोड़ों खेलेंगे, तो उसके लिए खेल उपकरण भी चाहिएं। पूरे विश्व में खेल बहुत बड़ा उद्योग बन कर उभरा है। हमारे देश में आज खेल उपकरणों का उद्योग अरबों रुपए का कारोबार हर वर्ष कर रहा है। खेल किट व खेल उपकरणों के बाजार में अच्छे से अच्छा व घटिया से घटिया सामान उपलब्ध है। जब सरकारी स्तर पर खेल सामान खरीदा जाता है तो कीमत बढिया या मध्यम स्तर के सामान की होगी और सामग्री निम्न दर्जे की होगी। इस तरह मूल्य उच्च क्वालिटी का तय कर शेष राशि हड़प ली जाती है। व्यापारी व सामग्री खरीदने वाले अधिकारी मिलकर अधिकांश राशि को चट कर जाते हैं। प्रदेश के महाविद्यालयों में जहां अधिकतर खेल सामग्री महाविद्यालय प्रशासन स्वयं खरीदता है, वहीं पर कुछ खेल सामान पहले शिक्षा निदेशालय मटीरियल्स एण्ड सप्लाई के अंतर्गत खरीद कर महाविद्यालय को दिया जाता था और अब जैम के माध्यम से खरीदा जा रहा है। मटीरियल्स एण्ड सप्लाई के अंतर्गत खरीदा गया खेल सामान बिल्कुल घटिया किस्म का मिलता रहा है। निम्न दर्जे के हाई जम्प व कबड्डी मैट, मुक्केबाजी रिंग व अन्य खेलों के घटिया उपकरण इसके उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत खरीदे जिम एक साल तो दूर, कुछ महीनों बाद ही कबाड़ हो जाते हैं। लाखों रुपए का खेल सामान तो खरीद लिया, मगर यह कोई नहीं सोचता है कि यह काम में भी लाया जा सकता है या नहीं? इस खेल सामान को खरीदने के लिए बनी कमेटी में निदेशालय के अधिकारी व बाबू होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद ही कोई खेल खेला हो, और जो थोड़ा बहुत खेल खेले हैं और खेल सामान की परख भी रखते हैं, वे भी अपने थोड़े लाभ के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। आज जब खेल खेल में स्वास्थ्य स्कीम के अंतर्गत कई करोड़ रुपयों की कृत्रिम प्ले फील्ड जूडो, कुश्ती व खो-खो आदि खेलों के लिए खरीद कर विद्यालयों व महविद्यालय को दी जा रही है। जहां भी खेल सामान खरीदना हो वहां पर खरीददारी के लिए जो कमेटी बने, उसमें जिस भी खेल का सामान खरीदना है उस खेल का प्रशिक्षक व कम से कम दो राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी भी विभागीय अधिकारियों के साथ हों। जिस संस्थान को सामग्री मिले वहां भी कमेटी देखे कि वह घटिया स्तर का तो नहीं दे दिया। अच्छी प्रशिक्षण सुविधा के अभाव में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी समय से पहले ही खेल को अलविदा कह जाते हैं और जिनके पास धन व साधन हैं, वे अच्छे प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश से पलायन कर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत कम प्रशिक्षण केन्द्र हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बनने के लिए स्कूल व कालेज समय में खिलाड़ी को अच्छी खेल सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। पूरे संसार में जहां के खिलाड़ी श्रेष्ठ हैं वहां पर स्कूल व कालेज स्तर पर बहुत ही उत्तम खेल सुविधाएं मुहैया हैं।

इस स्तर पर अगर हिमाचल प्रदेश में घटिया खेल सामान न खरीद कर उच्च क्वालिटी का खेल सामान खरीदा होगा तो स्तरीय खेल सुविधा होगी तो जहां जो खिलाड़ी प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव में खेल छोड़ देते हैं, वे अपने घर में रह कर खेल जारी रख सकते हैं। खेल सुविधाओं के लिए पलायन करने वालों को भी जब अपने ही राज्य में रह कर अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए सुविधा मिलेगी तो वे फिर क्यों अपना प्रदेश छोड़ेंगे। बात चाहे शिक्षा निदेशालय की हो या किसी भी संस्थान की, अब हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य चुका कर घटिया किस्म का खेल सामान खरीद कर करोड़ों रुपए की बंदरबांट को बंद करके असली खेल सामान खरीदना होगा।

भूपिंद्र सिंह

विकसित देश जैसी स्वास्थ्य सुविधा के लिए डॉक्टरों और बिस्तरों की संख्या में करनी होगी बढ़ोतरी : फिक्की EY की रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

वर्ष 2014 के बाद हर साल 5.9 प्रतिशत की दर से मेडिकल कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2005 में देश में एलोपैथ के पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या 660801 थी जो वर्ष 2022 में बढ़कर 1308009 हो गई। वर्ष 2014-15 में 398 मेडिकल कॉलेज थे और इन कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 45456 सीटें थी।

नई दिल्ली। सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन स्वास्थ्य सेक्टर में इस दिशा में काफी काम करने की जरूरत है। औद्योगिक संगठन फिक्की और रिसर्च एजेंसी ईवाई की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विकसित देशों की तरह स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए डाक्टर, नर्स की संख्या के साथ अस्पताल में बिस्तर की संख्या में भारी बढ़ोतरी करनी होगी।

विकसित देशों में उपलब्ध सुविधा के पास पहुंचने के लिए अस्पतालों में 30 लाख बिस्तर जोड़ने होंगे तो नर्सों की संख्या 1.25-1.5 करोड़ तक पहुंचानी होगी। डॉक्टरों की संख्या को भी 50 लाख के पार ले जाने की आवश्यकता है।

सभी जिलों में बनाने होंगे मेडिकल कॉलेज

रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में देश भर में 60,621 सरकारी अस्पताल थे जहां बिस्तरों की संख्या 8,49,206 थी। वैसे ही, वर्ष 2022 में देश में 36,14,000 नर्स तो 13,08,009 एलोपैथ डॉक्टर पंजीकृत थे। रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देश बनने के लिए देश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनी होगी और लोगों की जेब पर दवा खर्च का भार कम करना होगा। देश की 100 प्रतिशत आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाना होगा। हालांकि पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य सुविधा के प्रति सरकारी खर्च बढ़ने के साथ अस्पताल, डॉक्टर, नर्स जैसी तमाम स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2003-04 में जीडीपी का 0.9 प्रतिशत हेल्थ केयर पर खर्च किया गया जो वर्ष 2014-15 में जीडीपी का 1.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2022-23 में यह खर्च जीडीपी के 2.3 प्रतिशत तक पहुंच गया। स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी का यह परिणाम हुआ कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 के दौरान इलाज के लिए अपनी जेब की क्षमता से बाहर जाकर किए जाने वाले खर्च में 20 प्रतिशत की कमी आई।

वर्ष 2014 के बाद हर साल 5.9 प्रतिशत की दर से मेडिकल कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2005 में देश में एलोपैथ पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या 6,60,801 थी जो वर्ष 2022 में बढ़कर 13,08,009 हो गई। वर्ष 2014-15 में 398 मेडिकल कॉलेज थे और इन कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 45,456 सीटें थी। वर्ष 2023-24 में मेडिकल कॉलेज की संख्या 706 तक पहुंच गई और इन कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 1,09,145 सीट है।

चालू वित्त वर्ष में 500 अरब डॉलर के पार जा सकता है वस्तु निर्यात, अमेरिका और यूरोप की होगी अहम भूमिका

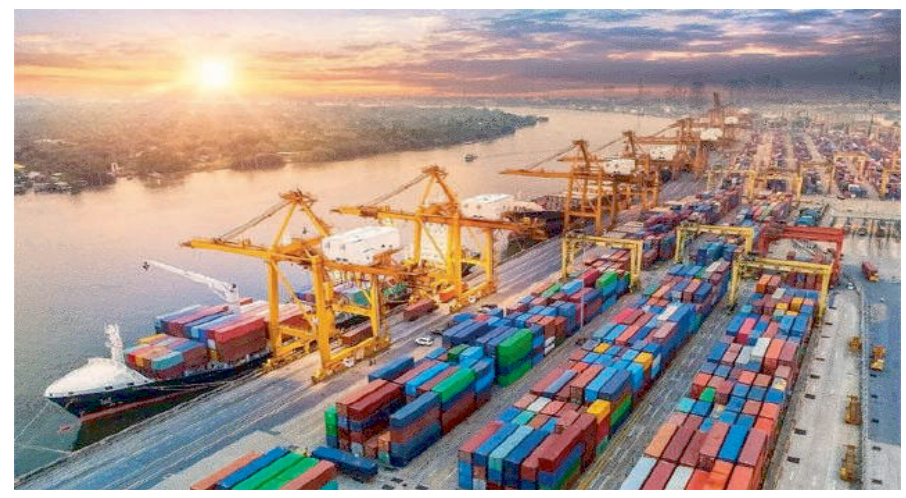

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सेवा निर्यात भी बढ़कर 390-400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को अपना निर्यात बढ़ने में अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक देशों की मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग और फार्मा क्षेत्र निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

देश का वस्तु निर्यात 60-70 अरब डॉलर बढ़कर 500 अरब डॉलर के पार जा सकता है। निर्यातकों के संगठन फियो ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक मांग में लगातार सुधार से देश के वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी होगी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का वस्तु निर्यात तीन प्रतिशत घटकर 437.1 अरब डालर रहा है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सेवा निर्यात भी बढ़कर 390-400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को अपना निर्यात बढ़ने में अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक देशों की मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इंजीनियरिंग और फार्मा क्षेत्र निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

हालांकि, उन्होंने श्रम आधारित क्षेत्रों जैसे कपड़े, फुटवियर और जेम एंड ज्वेलरी के प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 2030 तक ई-कॉमर्स के माध्यम से 300 अरब डॉलर तक का निर्यात बढ़ाए जाने की संभावना है।

इन 8 शहरों में 10 प्रतिशत बढ़ीं घरों की कीमतें, बेंगलुरू में सबसे ज्यादा है दाम

जनवरी-मार्च 2024 के दौरान टॉप आठ शहरों में आवास की औसत कीमतों में सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। बेंगलुरु में सबसे अधिक 19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10377 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं जो पिछले साल की समान अवधि में 8748 रुपये प्रति वर्ग फीट थी। दिल्ली-एनसीआर में आवास की कीमतें 16 प्रतिशत बढ़ी है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि इस साल जनवरी-मार्च के दौरान टॉप आठ शहरों में आवास की औसत कीमतों में सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसमें बेंगलुरु में सबसे अधिक 19 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। रीयलटर्स की संस्था क्रेडाई, रीयल एस्टेट कंसल्टेंट कोलियर्स इंडिया और डेटा एनालिटिक फर्म लियासेस फोरास ने एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा कि इन आठ शहरों में कीमतें 4 फीसदी से 19 फीसदी तक बढ़ी हैं। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-मार्च 2024 में बेंगलुरु में औसत आवास की कीमतें सालाना 19 प्रतिशत बढ़कर 10,377 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं, जो पिछले साल की समान अवधि में 8,748 रुपये प्रति वर्ग फीट थी।

लियासेस फोरास के प्रबंध निदेशक, पंकज कपूर ने कहा कि भारत के शीर्ष 8 शहरों में, मजबूत बिक्री और नई आपूर्ति की शुरूआत के साथ, संपत्ति की कीमतों में साल-दर-साल 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

उन्होंने कहा कि आवास की कीमतों में 19 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ बेंगलुरु सबसे आगे है, इसके बाद दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और पुणे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कपूर ने कहा कि लक्जरी मांग, आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और रणनीतिक लॉन्च जैसे कारक इन बढ़ोतरी को प्रेरित करते हैं। मध्यम मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के साथ, रियल एस्टेट क्षेत्र को सामर्थ्य के कारण मांग बनाए रखने की उम्मीद है।

कपूर ने कहा कि कीमतें 10-15 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जिससे सामर्थ्य और मुद्रास्फीति-समायोजित कीमतों के बीच का अंतर कम हो जाएगा। क्रेडाई नेशनल के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा कि आवास की कीमतों में वृद्धि देश भर में घर खरीदारों द्वारा विशेष रूप से प्रीमियम और लक्जरी आवास में मजबूत आवास मांग का प्रत्यक्ष परिणाम है।

ईरानी ने कहा कि ये सीधे तौर पर न केवल एक स्थिर ऋण पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हैं, बल्कि विभिन्न सूक्ष्म बाजारों के उद्भव से भी जुड़े हैं जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्राथमिक लाभार्थी रहे हैं - जिसने आवासीय अचल संपत्ति में मांग-आपूर्ति की गतिशीलता को बदल दिया है और हमें इसकी उम्मीद नहीं है वित्त वर्ष 24/25 में भी गति धीमी रहेगी।

FY 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा भारत ! संजीव सान्याल बोले- वित्तीय प्रणाली के साथ ना हो खिलवाड़

परिवहन विशेष न्यूज

सान्याल ने कहा कि देश के कमजोर निर्यात सहित विभिन्न बाधाओं को देखते हुए 7 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर भारत के लिए बहुत अच्छी विकास दर होगी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के सदस्य संजीव सान्याल ने गुरुवार को कहा कि भारत 2024-25 में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

पार होगा 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा!

सान्याल ने कहा कि देश के कमजोर निर्यात सहित विभिन्न बाधाओं को देखते हुए 7 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर भारत के लिए 'बहुत अच्छी' विकास दर होगी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, रतो, इस वित्तीय वर्ष में हम 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका आकार नाममात्र के संदर्भ में लगभग 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

जापान को पछाड़ेगा भारत

सान्याल ने कहा कि जापान अब 4.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ हमसे थोड़ा ही आगे है। सान्याल ने कहा, रतो, या तो अगले साल की शुरुआत में या आप जानते हैं कि इस साल, हम जापान को पार कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जहां एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) और फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर 7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.8 फीसदी विकास दर का अनुमान लगाया है।

वित्तीय प्रणाली के साथ ना हो खिलवाड़: सान्याल

सान्याल ने इस बात पर जोर दिया कि विकास को समर्थन देने की कोशिश में वित्तीय प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, "अपनी राजकोषीय प्रणाली, अपनी मौद्रिक प्रणाली, अपने चालू खाते वगैरह के साथ खिलवाड़ न करें।" रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण पर एक सवाल के जवाब में सान्याल ने कहा कि यह रुपये को कठोर मुद्रा में बदलने के बारे में है।

फोर्ब्स की लिस्ट में अक्षित बंसल, राघव अरोड़ा और भाग्यश्री जैन का नाम भी शामिल, देखें लिस्ट

प्रतिष्ठित मैग्जीन फोर्ब्स (Forbes) ने 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एशिया के टॉप एंटरप्रेन्योर लीडर्स इनोवेटर्स के नाम शामिल हैं जो इंडस्ट्री को बदलने की क्षमता रखते हैं। मैग्जीन ने अलग-अलग कैटगरी के 900 लीडर्स की लिस्ट जारी की है। उनका कहना था उन्होंने 4000 में से 900 लोगों को सलेक्ट किया है।

नई दिल्ली। Forbes ने अपनी 30 Under 30 Asia लिस्ट शेयर कर दी है। इस लिस्ट में उसने एशिया के 300 युवा एंटरप्रेन्योर (उद्यमी), नेता और इनोवेटर्स शामिल है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है। मैग्जीन के मुताबिक ये सभी अपने इनोवेशन के जरिए इंडस्ट्री को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस लिस्ट में भारतीय स्टार्टअप Statiq के को-फाउंडर अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा और The Disposal Company कंपनी के फाउंडर भाग्य श्री जैन भी शामिल हैं। यहां हम आपके साथ इस लिस्ट में शामिल भारतीय के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

इन भारतीयों का नाम शामिल

इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क पर काम करने वाली कंपनी Statiq के को-फाउंडर्स अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल हैं।

कंपनी को साल 2024 में 27.5 मिलियन डॉलर फंड मिला है। कंपनी इस साल करीब 9.9 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमा सकती है। कंपनी का लक्ष्य है कि वे 2025 तक देशभर में 16,000 चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करेगा।

The Disposal Company कंपनी की फाउंडर भाग्य श्री जैन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। भाग्यश्री जैन साल 2020 से प्लास्टिक न्यूट्रैलिटी को फोकस कर रही हैं। उनका मानना है कि कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों को प्लास्टिक फूटप्रिंट कम करने पर फोकस करना चाहिए।

जापान की सबसे कम उम्र की मेयर

इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इनमें K-pop गर्ल बैंड Ive, जापान की सबसे कम उम्र की मेयर Ryosuke Takashima का नाम भी शामिल है। फोर्ब्स ने बताया कि इस लिस्ट को तैयार करने के लिए उसने एशिया के 4000 कैंडिडेट्स को शामिल किया था। मैग्जीन की ज्यूरी जिसमें रिपोर्टर, एडिटर और स्वतंत्र जज ने फंडिंग, रेवेन्य, सोशल इंपैक्ट, और दूसरे पैमानों पर 900 नाम फाइनल किए हैं।

30 Under 30 Asia 2024 की खास बातें

इस लिस्ट के लिए अलग-अलग कैटगरी बनाई गई थी। यहां हम आपको हर कैटगरी में पहले पायदान पर आए कैंडिडेट के नाम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

Industry, Manufacturing & Energy: अक्षित बंसल (29) और राघव अरोड़ा (28), को-फाउंडर Statiq – भारत

Social Impact: भाग्यश्री जैन (29), फाउंडर The Disposal Company – भारत

Finance & Venture Capital: एलीना नदीम (29), फाउंडर EduFi – पाकिस्तान

Arts : क्लेन डॉसन (29), को-फाउंडर Gym Bod - ऑस्ट्रेलिया

Entertainment & Sports: वॉइस ऑफ बैकप्रोट, मेटल बैंड - इंडोनेशिया

Media, Marketing & Advertising: एरिका इंग (25) कॉमिक आर्टिस्ट – मलेशिया

Retail & Ecommerce: योमी ह्वांग (29) को-फाउंडर YOLO – साउथ कोरिया

Enterprise Technology: जू वीयांग (27) फाउंडर Small Eel – चीन

Healthcare & Science: जांग जीक्यून (28), फाउंडर Tidetron Bioworks – चीन

Consumer Technology: जॉनसन लिम (29) को-फाउंडर GetGo – सिंगापुर

देश की कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग क्षमता में भारी वृद्धि की तैयारी- अगले डेढ़ वर्ष में 10000 जीपीयू लगाएगा भारत

जीपीयू को आज कंप्यूटर की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग तकनीक माना जा रहा है। गेमिंग कारोबार कंटेंट निर्माण मशीन लर्निंग आदि का इस्तेमाल व्यक्तगित स्तर पर करना हो या वाणिज्यक तौर पर जीपीयू की क्षमता को बेहद आवश्यक माना जा रहा है। कंप्यूटर के क्रीयेटिव इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के बढ़ते उपयोग की वजह से ही इसे आवश्यक माना जा रहा है।

नई दिल्ली। अगली केंद्र सरकार देश की मौजूदा कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने का काम प्राथमिकता के तौर पर लेगी। इस बात के संकेत नीति आयोग के पूर्व सीईओ और जी-20 के शेरपा अमिताभ कांत ने दिए। गुरुवार को उन्होंने बताया है कि भारत अगले 18 महीनों के भीतर 10 हजार ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) की खरीद करने जा रही है।

इस बारे में होने वाले निवेश को रणनीतिक निवेश बताते हुए कांत ने कहा है कि देश की मौजूद कंप्यूटिंग सिस्टम को सक्षम बनाने के लिए यह जरूरी होगा। इस बारे में भारत सरकार की दुनिया की कुछ दिग्गज प्रोसेसिंग यूनिट बनाने वाली कंपनियों जैसे एनवीडिया आदि से बात अंतिम दौर में है और आम चुनाव के बाद जून में केंद्र सरकार के गठन के बाद विस्तृत घोषणा होगी। इस बारे में भारत सरकार की तरफ से भी तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जो हाल ही में घोषित इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) मिशन के तहत होगा।

जीपीयू को आज कंप्यूटर की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग तकनीक माना जा रहा है। गेमिंग, कारोबार, कंटेंट निर्माण, मशीन लर्निंग आदि का इस्तेमाल व्यक्तगित स्तर पर करना हो या वाणिज्यक तौर पर, जीपीयू की क्षमता को बेहद आवश्यक माना जा रहा है। कंप्यूटर के क्रीयेटिव इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के बढ़ते उपयोग की वजह से ही इसे आवश्यक माना जा रहा है।

भारत में अभी तकरीबन 700 के करीब ही जीपीयू है। कांत ने गुरुवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि सरकार देश की कंप्यूटिंग क्षमता में भारी बढ़ोतरी करने को तैयार है। इसके लिए अगले 18 महीनों में 10 हजार जीपीयू की खरीद की जाएगी। इस रणनीतिक निवेश से हमारी कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग क्षमता हमारी डाटा इस्तेमाल करने की क्षमता के अनुसार हो जाएगी। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से डाटा निर्माण कर रहा है। अमूमन दुनिया का 20 फीसद डाटा भारत में बन रहा है।

कांत आगे लिखते हैं कि दुनिया की कुल एआई परियोजनाओं का भी 19 फीसद भारत में है। यह बताता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एआई के इस्तेमाल करने में भारत की क्षमता कितनी है। एआई की वजह से भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में बहुत बदलाव आएगा व मानव संसाधन विकास में भारत की स्थिति सुधरेगी।

मार्च, 2024 में ही पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में 10,372 करोड़ रुपये के एआई मिशन को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत दुनिया भर की डाटा प्रोसेसिंग कंपनियों को भारत में जीपीयू लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के साथ बातचीत आगे बढ़ चुकी है और सरकार गठन के बाद इसकी सबसे पहले घोषणा होगी।

पाकिस्तान की अब खैर नहीं! वायुसेना को जुलाई तक मिलेगा पहला LCA मार्क-1A विमान, HAL और भी ऑर्डर मिलने की उम्मीद

भारतीय वायुसेना को देश का पहला एलसीए मार्क 1ए लड़ाकू विमान इस साल जुलाई तक मिलने की उम्मीद है। रक्षा अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि भारतीय वायुसेना और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने हाल ही में एलसीए लड़ाकू परियोजना की समीक्षा की और अब इसे इस साल जुलाई तक वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना को देश का पहला एलसीए मार्क 1ए लड़ाकू विमान इस साल जुलाई तक मिलने की उम्मीद है। एचएएल की ओर से इस विमान को पहले फरवरी-मार्च में भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें थोड़ी देरी हुई।

जुलाई तक वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद

रक्षा अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि भारतीय वायुसेना और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने हाल ही में एलसीए लड़ाकू परियोजना की समीक्षा की और अब इसे इस साल जुलाई तक वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है।

पीएम मोदी को भी किया जा सकता है आमंत्रित

उन्होंने कहा कि एचएएल ने पिछले महीने लड़ाकू विमान की पहली उड़ान भरी थी और वायुसेना को सौंपे जाने से पहले अगले कुछ हफ्तों में कई अन्य एकीकरण परीक्षण पूरे कर लिए जाएंगे। स्वदेशी लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल करना सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम होगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय ने HAL को दिया है टेंडर

प्रधानमंत्री के कार्यभार संभालने के बाद एलसीए मार्क 1ए परियोजना की परिकल्पना की गई थी। 83 विमानों के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का एक आर्डर पहले ही दिया जा चुका है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 97 विमानों के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का एक और आर्डर दिए जाने की उम्मीद है।

रक्षा मंत्रालय ने 97 मेड-इन-इंडिया एलसीओ मार्क 1ए फाइटर जेट की खरीद के लिए एचएएल को पहले ही टेंडर जारी कर दिया है। यह टेंडर भारत सरकार का स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर को दिया अब तक का सबसे बड़ा आर्डर है।

हाल ही में सरकारी अधिकारियों ने सूचित किया था कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के मिग-21, मिग-23 और मिग-27 के बेड़े को बदलना है, जिन्हें या तो चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है या जल्द ही चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है।

भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के विरोध में मणिपुर, मिजोरम में निकाली गईं रैलियां

म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) को रद करने और पड़ोसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के सरकार के फैसले की निंदा करने के लिए बड़ी संख्या में कुकी समुदाय के लोगों ने गुरुवार को मणिपुर और मिजोरम में रैलियां निकालीं। केंद्र ने सीमा पार से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को रद करने की घोषणा की है।

इंफाल। म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) को रद करने और पड़ोसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के सरकार के फैसले की निंदा करने के लिए बड़ी संख्या में कुकी समुदाय के लोगों ने गुरुवार को मणिपुर और मिजोरम में रैलियां निकालीं।

भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा

केंद्र ने सीमा पार से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को रद करने की घोषणा की है। एफएमआर लोगों को अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 16 किमी तक पार करने की अनुमति देता है।

सैकड़ों लोगों ने निकाली रैली

मणिपुर और केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में जातीय संघर्ष के कारणों में से एक के रूप में सीमा पार से अवैध रूप से आने वालों को जिम्मेदार ठहराया था। जातीय संघर्ष में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। कुकी समुदाय से जुड़े सैकड़ों लोगों ने मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में रैली निकाली। साथ ही हजारों प्रदर्शनकारियों ने कई जुलूसों में हिस्सा लिया। मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ 390 किमी और 510 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं।

7,000 प्रदर्शनकारियों ने रैली में लिया भाग

मिजोरम में जो यूनिफिकेशन आर्गेनाइजेशन (जोरो) द्वारा आयोजित रैलियां चम्फाई और लुंगलेई जिलों में आयोजित की गईं। जोरो एक मिजो समूह है जो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार की सभी चिन-कुकी-मिजो-जोमी जनजातियों को एक प्रशासन के तहत लाकर उनका पुनर्मिलन चाहता है। जोरो महासचिव एल रामदीनलियाना रेंथलेई ने कहा कि वफाई और आसपास के गांवों के हजारों लोगों ने सुबह जुलूस निकाला, जबकि लगभग 7,000 प्रदर्शनकारियों ने जोखावथर रैली में भाग लिया।

अडाणी टोटल गैस (एटीजीएल), अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (एबीटीए) ने भारत क्लीन इकोसिस्टम को समर्थन करने के लिए एमओयू साईन किया

परिवहन विशेष न्यूज

भिवानी। भारत की अग्रणी शहरी गैस वितरण कंपनी, अडाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल), वर्तमान में अपने संयुक्त उद्यम भागीदार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 19 भौगोलिक क्षेत्रों सहित 52 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भारत के सडक़ परिवहन बिरादरी के कल्याण के लिए एक ट्रस्ट है जो संगठित भारतीय सडक़ परिवहन व्यवसाय के लगभग 62 फीसदी का प्रतिनिधित्व करता है, ने एक एमओयू साईन किया है जिसके तहत ्रञ्जत्रु और ्रक्चञ्ज्र विकास का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि परिवहन समुदाय को शिक्षित एवं जागरूकता पैदा करके सीएनजी और एलएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर ड्राइवर समुदाय और ट्रांसपोर्टरों को प्रशिक्षण प्रदान करें। ट्रांसपोर्टरों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें और वाहनों को पारंपरिक ईंधन से सीएनजी/एलएनजी में बदलने की सुविधा प्रदान करें। पूरे देश में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ ईंधन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करना।

ईडी एवं सीईओ एटीजीएल सुरेश पी मंगलानी ने कहा कि हम स्वच्छ ईंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसमें योगदान देने के लिए एबीटीए जैसे ट्रस्ट के साथ जुडक़र खुश हैं। एमओयू के तहत एटीजीएल और एबीटीए देश में स्वच्छ ईंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करेंगे। कम उत्सर्जन, बेहतर माइलेज और कम रखरखाव लागत के कारण परिचालन की कम लागत, कम शोर के कारण बेहतर ड्राइविंग आराम और मौजूदा बीएस-3 और बीएस-4 के विस्तारित जीवन के कारण बड़े संचालकों को सीएनजी और एलएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन से लाभ होने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के.शर्मा ने कहा कि हमारा अडाणी ग्रुप के साथ समझौता लंबे समय तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की भलाई के लिए काम करता रहेगा। ट्रांसपोर्टरों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें और वाहनों को पारंपरिक ईंधन से सीएनजी/एलएनजी में बदलने की सुविधा प्रदान करें। पूरे देश में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ ईंधन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करना इस एमओयू में शामिल है। एमओयू साईन करने वालों में गैस सोर्सिंग व बिजनेस डेवलपमेंट के नेशनल हेड राहुल भाटिया, बिजनेस प्लानिंग व एलएनजी के हेड नरेश सिसोदिया, टेक्निकल सर्विसेज के हेड नविन्द्र बेदी, हेल्थ सेफ्टी एंड पर्यावरण के हेड प्रणब घोष, एलएनजी के वरिष्ठ प्रबंधक भारत ओझा, सीईओ ऑफिस के प्रबंधक ऋषभ लोहिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के.शर्मा, महासचिव अशोक कुमार, सलाहकार सुनील शर्मा, संरक्षक गुजरात केसरी शर्मा, महासचिव गुजरात सुनील पंवार शामिल थे।

पांच दिनों तक लू की चपेट में रहेगा उत्तर भारत, यूपी समेत इन राज्यों में 46 के पार पहुंच सकता है अधिकतम तापमान

भारत मौसम विभाग (IMD) को आशंका है कि दिल्ली का तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच सकता है। आईएमडी ने उत्तर-पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले पांच दिनों तक लू राजस्थान और गुजरात से होते हुए पूरे उत्तर भारत को चपेट में ले लेगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। बलूचिस्तान से चलने वाली शुष्क हवा ने उत्तर भारत में मौसम के मिजाज को भी गर्म कर दिया है। अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा लू (हीट वेव) की चपेट में आने वाला है।

45 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है दिल्ली का तापमान

भारत मौसम विभाग (IMD) को आशंका है कि दिल्ली का तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच सकता है। सावधानी के तौर पर आईएमडी ने उत्तर-पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से के लिए लू का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। शनिवार से तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। ऐसे में गर्मी से संबंधित बीमारियां बढ़ने की आशंका है। किसी क्षेत्र विशेष में सामान्य से चार डिग्री से अधिक तापमान हो जाने पर वहां लू की स्थितियां बनती हैं।

उत्तर भारत लू चलने की संभावना

मौसम के लिहाज से पूरा देश अभी दो हिस्सों में बंटा हुआ है। दक्षिण भारत में अभी तेज बारिश हो रही है तो उत्तरी हिस्से में प्रचंड गर्मी के हालात बन रहे हैं। अगले पांच दिनों तक लू राजस्थान और गुजरात से होते हुए पूरे उत्तर भारत को चपेट में ले लेगी। राजस्थान के गंगानगर में बुधवार को अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री था। अभी और ऊपर चढ़ सकता है।

कई राज्यों में प्रचंड लू का खतरा

निजी एजेंसी स्काईमेट का अनुमान है कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से का अधिकतम तापमान कहीं-कहीं 46-47 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे हवा अधिक शुष्क हो जाएगी। इसमें नमी की मात्रा लगभग नहीं के बराबर होगी। जब यह गर्म हवा दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर आएगी तो कई जिलों में प्रचंड लू चलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसी दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है।

इन राज्यों में पड़ सकता है गर्म हवा का असर

राजस्थान एवं गुजरात से आने वाली गर्म हवा का असर उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से, बिहार, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, झारखंड एवं ओडिशा तक पड़ सकता है। यहां का तापमान तेजी से ऊपर जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी बारिश की स्थिति अब थमने वाली है। अगले दो दिनों में मुरैना, भिंड, टिकमगढ़, सागर, दतिया और ग्वालियर जिले में लू चलने लग सकती है।

इन राज्यों में पड़ने वाली है प्रचंड गर्मी

हरियाणा के जिले रेवाड़ी, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी एवं मेवात के अधिकतम तापमान में सामान्य से छह डिग्री तक उछाल आ सकता है। पंजाब में दो दिनों तक लू की स्थितियां बनी रहेंगी। इस दौरान फिरोजपुर, फजिल्का, मोगा, मनसा, तरन-तारण, फरीदकोट एवं मोगा जिलों में लू चल सकती है। गुजरात में भी अगले तीन दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है।

IMD ने यूपी को लेकर जारी किया अपडेट

मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि सामान्य तौर पर मई के मध्य में दो से तीन दिनों तक उत्तर भारत में लू चलती है। किंतु इस बार पांच से छह दिनों तक ऐसी स्थिति रह सकती है। राजस्थान, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की आशंका है। दक्षिणी यूपी भी गर्मी से बेहाल हो सकता है।

इन राज्यों में हो सकती है बारिश

बिहार-झारखंड एवं बंगाल में गर्मी का असर तीन-चार दिनों तक ही रहेगा। उसके बाद यहां पूर्व मानसून बारिश का सिलसिला प्रारंभ हो सकता है। इस बीच, पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है। इससे हिमालय क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। इसके असर से तीन-चार दिनों के दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड में वर्षा की संभावना है।

'कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिग्रहण होगा असंवैधानिक', सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो निजी संपत्तियों का अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक होगा।कोर्ट ने कहा यदि राज्य और उसकी मशीनरी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के बदले मुआवजे के भुगतान की वैधानिक योजना भी उचित नहीं होगी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो निजी संपत्तियों का अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक होगा। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य और उसकी मशीनरी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के बदले मुआवजे के भुगतान की वैधानिक योजना भी उचित नहीं होगी।

कोलकाता नगर निगम की अपील खारिज कर दी

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कोलकाता नगर निगम की अपील खारिज कर दी। शहरी निकाय ने कोलकाता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के उस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष कोर्ट की शरण ली थी, जिसमें एक पार्क के निर्माण के लिए शहर के नारकेलडांगा नॉर्थ रोड पर एक संपत्ति के अधिग्रहण को रद्द कर दिया था।

अधिग्रहण पर आपत्तियों को सुनना राज्य का कर्तव्य

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नगर निगम के पास अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट प्रविधान के तहत कोई शक्ति नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 300ए के तहत भूमि मालिक को प्रक्रियात्मक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह संबंधित व्यक्ति को सूचित करे कि वह उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है। साथ ही अधिग्रहण पर आपत्तियों को सुनना भी राज्य का कर्तव्य है।

अटल भू जल योजना अंतर्गत QCI टीम के द्वारा भौतिक सत्यापन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा अटल भूजल योजना के अंतर्गत पंचायत समिति शाहपुरा की तहनाल एवम आमली कला ग्राम पंचायतो में राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई नई दिल्ली द्वारा नियोजित (Quality Quancil of India) टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 मे ग्राम जल सुरक्षा योजना में समाहित कार्यों के सत्यापन हेतु ग्राम पंचायत भवन मे अटल भूजल योजना के लाभार्थियों से मिलकर योजना के अंतर्गत सम्पादित किये गए।

इस दौरान पाइपलाइन, ड्रिप, फव्वारा, फार्म पोंड, एनीकट इत्यादी कार्यो का भौतिक अवलोकन किया गया।

अवलोकन के दौरान जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, भीलवाड़ा से कृषि विशेषज्ञ राधेश्याम कुमावत एवं टीम लीडर राजेश कुमार के साथ सरपंच, वीडीओ, कृषि पर्यवेक्षक, वी डबलयू एस सी सदस्यगण, लाभार्थियो व अन्य ग्रामजन उपस्थित रहे।

ज़िला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में सुनी जन समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश

शाहपुरा। आमजन की फ़रियादो का निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को ग्राम पंचायत तहनाल में रात्रि चौपाल आयोजित कर जनसुनवाई की। कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में ग्राम पंचायत क्षेत्र की पेयजल, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी पोषाहार व्यवस्था के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली। रात्री चैपाल में राजस्व, विद्युत, सामाजिक एवं न्याय विभाग, पंचायती राज, जलदाय, रसद, स्वास्थ्य विभागों से संबंधित 46 प्रकरण प्राप्त हुए, प्राप्त सात प्रकरणों के जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिये। रात्रि चौपाल में पुलिस अधीक्षक राजेश कावट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकेश मीना, उपखंड अधिकारी निरमा बिश्नोई, विकास अधिकारी चुनाराम विश्नोई, तहसीलदार रामकुमार पूनिया, सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण व ग्रामवासी मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023